जैसा मैंने देखा कि प्रत्येक वर्ष इसी मुद्दे पर, shifting of the courts from one place to another place, इस तरह की बात आती है। होना यह चाहिए कि जो वकीलों की एक नेसेसिटी है, उसे भी देखा जाना चाहिए। यह बात तो समझ में आती है कि सरकार का एक पक्ष है, लेकिन उसके बारे में कन्विन्स हों और एक बाइफरकेशन इस प्रकार का हो, जो सर्वमान्य हो सके। मुझे लगता है कि यह एक गंभीर विषय है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

Need to ameliorate Economic Condition of Farmers in the backdrop of Natural Calamities

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, it is 2.30 now, which is time for Private Members' Business. We were discussing Resolution moved by Shri V. Narayanasamy on the welfare of farmers. Dr. Faguni Ram.

डा॰ फागुनी राम (बिहार): उपसभापति जी, बहुत शुक्रिया। आपने किसान जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का जो मौका दिया है, उसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और नारायणसामी जी को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बड़े ही डिटेल के साथ यह रेजोलूशन सदन के सामने विचारार्थ रखा है।

महोदय, किसान हमारे देश की रीढ़ है। कहा जाता है- ''अपना हिंदुस्तान कहां, वह बसा हमारे गांव में''। किसान का मतलब है खेती और खेती का पर्याय है किसान। खेती से किसान जाने जाते हैं और किसान से खेती जानी जाती है। आज इन दोनों की हालत पर विचार करने की जरूरत है। हम क्रम-क्रम से देखेंगे कि इनकी हालत क्या है? खेती में प्रयुक्त होने वाली बहुत सी चीजें हैं, जैसे उनके लिए बीज चाहिए, बीजाई, रोपाई, जुताई चाहिए और उसके बाद उसका-रख-रखाव चाहिए। इसके लिए एरीगेशन चाहिए, किसान चाहिए, बैल चाहिए, मज़दूर चाहिए और इन सब चीजों की जरूरत खेती के लिए पड़ती है। अब एक एक चीज पर विचार करके हम देखेंगे।

महोदय, भारत की 70 परसेंट आबादी गांवों में रहती है और इसलिए कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांवों में रहती है। यह बिल्कुल ठीक बात है। यह जो 70 परसेंट आबादी गांवों में रहती है, अब उनका विकास देश का विकास है, उनकी प्रगति देश की प्रगति है, उनकी संतुष्टि देश की प्रगति की द्योतक है। जहां उनकी संतुष्टि, जन-मानस या जन-साधारण की संतुष्टि की बात हो, तो वहां यह प्रश्न विचारणीय है, जो एक महत्वपूर्ण बात है। आप देखिए, मोटा-मोटी किसान तीन-चार तरह के होते हैं। एक तो किसान सीमांत होते हैं, दूसरे लघु किसान होते हैं, तीसरे मध्यम

किसान होते हैं और चौथे उच्च किसान होते हैं। सिंचाई की नजर से देखें, तो बंजर खेती होती है, असिंचित खेती होती है, अल्प-सिंचित खेती होती है, सूखी खेती होती है, सिंचाई-पूर्ण खेती होती है और फिर सूखाढ़ खेती होती है, बाढ़ की खेती होती है। हम लोग यह भी देखते हैं कि हमारी खेती भारतीय मानसून के साथ जुड़ी हुई है। अगर मानसून की दया हो गई, तो किसान की खेती ठीक हो जाती है और अगर मानसून की, बारिश की दया नहीं होती तो हमारे किसान बर्बाद हो जाते हैं। हम जब देश की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से किसानों की बात करते हैं। हाऊस में अभी बहुत बार चर्चा हुई है कि हमारे किसान कर्ज की मार से, हमारे किसान असंतुष्टि की मार से ग्रस्त हैं। किसान जो फसल पैदा करके देश को बनाता है, आज उसकी स्थिति खराब है और वह आत्महत्या तक करने पर मजबूर हो जाता है।

महोदय, हम बिहार के रहने वाले हैं। वर्ष 1967 में बिहार में अकाल पड़ा था। उस समय माननीया श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्राइम-मिनिस्टर थीं। उन्होंने भारत के सूखा-पीड़ित इलाकों का दौरा किया और दौरा करके एक सर्किट हाऊस में आफीसर्स के साथ, हम लोगों के साथ उस अकाल के बारे में बात करते हुए कहा था। उस समय अमरीका से वह सब निकाला हुआ गेहूं आता था, चावल का नाम नहीं था, झिनोरा जो माइको है, लोग वही किसी तरह से खाते थे। लोगों की तकलीफ देखकर उन्होंने कहा था कि अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से हम विदेश से अन्न नहीं मंगाने देंगे और हम अपने हिंदुस्तान के भाइयों, अपने हिंदुस्तान के लोगों, चाहे वे किसी वर्ग के हों, किसी समुदाय के हों, किसी इलाके के हों, किसी स्टेट्स के हों, उन्हें इस तरह भूख से नहीं मरने देंगे। ऐसा अकाल नहीं देखना पड़ेगा और उन्हें देश का अन्न मिलेगा और देश का अन्न हम लोग खाएंगे। यह थी उनकी हरित क्रांति की घोषणा। हरित क्रांति के दिनों में हमारे बाबू जी भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उस समय अकाल पड़ा था, संयोग से वे उस समय आरा में गए और वहां बारिश हुई तो लोगों ने कहा - बड़े किस्मत वाले मिनिस्टर हैं कि यहां सूखा पड़ा है, वे आरा के रेलवे मैदान में भाषण दे रहे हैं और बारिश हो रही है। तो इन लोगों ने मेहनत करके हरित क्रान्ति को चलाया। हरित क्रांति से ऐसा हुआ कि उसी साल 1967 में ही, जो लोग अग्रहन की फसल नहीं काट सके, टाइचून और कोई धान लाकर हम लोगों से गरमा धान उगवाया गया। हम लोग भी किसान हैं, हमारे बाबू जी भी किसान हैं, उससे हम सभी लोगों के घर में कुछ न कुछ चावल आ गया। जो चावल अग्रहन में आना चाहिए था, इंदिरा गांधी की कृपा से, एग्रीकल्चर मिनिस्टर की कृपा से वह चावल हम लोगों के घरों में आषाढ़ और श्रावण में आया। यह हरित क्रांति की देन थी। इस तरह से हरित क्रांति की तरक्की हुई, हरित क्रांति चली, लोगों ने सोचा कि इसकी तरक्की करना चाहिए। दूरदृष्टि, पक्का इरादा और लक्ष्य, ये उसके उद्देश्य थे और इसका लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा।

किसान के सामने पूंजी की समस्या है क्योंकि एग्रीकल्चर आजकल इन्वेस्टमेंट हो गया है। पहले पूंजी लगाइए तब अनाज पाइए। ऋण लीजिए तब मेहनत करके पहले ऋण वालों को

दीजिए और फिर अपने लिए खाइए। मैंने अभी कृषियों के बारे में बताया कि जहां बंजर भूमि है, वहां क्या पैदा होगा, जहां पर असिंचित भूमि है, वहां क्या पैदा होगा, जहां अर्धसिंचित भूमि है, वहां क्या पैदा होगा, फिर बाढ़ और सूखा, इसलिए मेरा कहना है कि किसानों पर प्रकृति की नेचर की और समाज की, सबकी मार पड़ती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे किसान की तरक्की, उनका उत्पादन ही हमारे देश के विकास की रीढ़ है, आगे बढ़ने का आधार है, 1967 में जब बाहर से अनाज आ रहा था, गल्ला आ रहा था, तब मिलो, जिनौरा, बाजरा, यह सब लोग खाने के लिए मजबूर हो रहे थे। उस समय हमने सुना था, विदेशों में दिखाया गया कि जानवर जब गेंहू या ऐसा कुछ खा लेता है और उसने जब अपनी विष्ठा की, तो उसको भी धोकर और उसमें गेंहू निकालकर, उसे चुनकर गरीब लोग खा रहे हैं। तो उस समय स्थिति इतनी खराब थी। मैडम श्रीमती इंदिरा गांधी को ममता आई, उनका वात्सल्य जागा और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि आगे से हम ऐसा नहीं होने देंगे और उन्होंने किसानों को प्रोत्साहन दिया। जहां खाने को नहीं मिलता था, जो जगह अकालग्रस्त थी, वह आज अन्न के मामले में किसी बदौलत आत्मनिर्भर है? हम किसानों की वजह से अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हैं, कृषक मजदूरों की वजह से हम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर है, साइंस एंड टैक्नोलॉजी तथा सुविधा के आधार पर हम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हैं। अब हम इसे एक-एक करके देखेंगे। किसानों को बीज चाहिए, ठीक है, पहले से अधिक उत्पादन वाले अच्छे बीज उनको दिए गए हैं, लेकिन वे बीज उनको कभी-कभी समय पर नहीं मिल पाते, कभी-कभी खाद उनको समय पर नहीं मिल पाती और रासायनिक खादों का बराबर प्रयोग करने से धरती की नेचुरल उर्वरा शक्ति कमजोर हो गई है। जहां किसान को एक बार खाद दी गई, वहां उसके खेत में बराबर खाद की जरूरत होती है और प्रत्येक साल उससे अधिक मात्रा में जरूरत होती है। इसके लिए किसान को पूंजी चाहिए, इसलिए पूंजी चाहिए क्योंकि पहले वह अपने घर और अपने घर के बदले ऋण लेकर उसे खेत में डालता है, भगवान के और किस्मत के आसरे पर और कहता है कि-किसान रोपे क्यारी उपजे लिलारी। किसान जब रोपता है तो क्यारी में रोपता है लेकिन जब उपज होती है उसकी किस्मत के अनुकूल। ऐसा देखा भी गया है कि एक गरीब की और बिना किस्मतवाले की पैदावार ऐसे ही रह जाती है और उसके एक डेरा के बाद भी किस्मतवाले का खेत खूब हरा-भरा रहता है, झूमता रहता है और वह फसल उसका मन मोह लेती है, जिसे देखकर वह गीत गाता रहता है। तो वह स्थिति है आज किसान की। इसलिए किसानों को समय पर कम ब्याज में ऋण मिलना चाहिए। जब एक-दो बार उसको ऋण मिला, लेकिन अगली बार उसकी फसल मर जाती है, चाहे अकाल के कारण, सूखे के कारण या किन्हीं अन्य प्राकृतिक कारणों से उसकी फसल नहीं हो पाती है, उस समय भी हमारे किसानों से बैंकों के या कर्जा देने वाले लोग बोलते हैं कि आप हमको कर्जे का पैसा दीजिए। आप सोचिए, एक तरफ

तो उसने अपनी पूंजी को खेत में लगा दिया और फिर भी फसल नहीं हुई, उसके बावजूद भी बैंक को अपना कर्ज वापस चाहिए। वह साधारण समझ वाला किसान इतनी बड़ी मार को बर्दाशत नहीं कर पाता है और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। यदि हमें उस किसान को आत्महत्या करने से बचाना है तो हमें स्वयं उसकी परिस्थिति के अनुकूल चलना होगा और यह देखना होगा कि वह अपनी परिस्थितियों के कारण आगे चल कर इतना मजबूर न हो जाए कि अपने आपको कुंठित या असहाय समझ लें और उसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई देने लगे, जिससे उसके मन में असंतोष और पीड़ा उत्पन्न हो जाए। इसलिए हम किसानों के लिए यह कहते है कि उन्हें यह सब मिलना चाहिए।

श्री उपसभापति: आप समाप्त कीजिए।

डा॰ फागुनी राम: सर, अभी तो मैंने शुरू ही किया है।

इसलिए उन्हें बीज दिए जाएं। खेती की पैदावार बहुत हद तक सिंचाई या मानसून के ऊपर निर्भर करती है। इसके लिए समुचित गर्मी और समुचित पानी यह दोनों ही चीजें चाहिए। कहीं पर अगर मेघालय के समान सदैव ही बादल घिरे रहते हों और सूर्य का प्रकाश न पड़ता हो तो फसल नहीं हो सकती है और यदि चेरापूंजी की तरह हर रोज बारिश ही होती रहती हो और वहां पर ठंडक प्राप्त न हो, तब उचित क्लाइमेट के अभाव में, आर्द्रता के अभाव में, बारिश होते हुए भी वहां पर फसल नहीं हो सकेगी। इसलिए जरूरत इस बात की है कि मौसम के अनुकूल किसान को जितनी बारिश चाहिए, जितना सूर्य का प्रकाश चाहिए, जिस प्रकार की हवा चाहिए, उसे वह सब मिलना चाहिए। किसान लोग इस बारें में कहते हैं कि

आवत आदर न दियो, जात दियो न हस्त
इह विधि दोनो गए, पाहू न ऊ गृहस्थ

अगर आते हुए अद्रा नक्षत्र में और जाते हुए हस्त नक्षत्र में पानी नहीं पड़ा तो गृहस्थ लोग चले जाते हैं और फिर फसल नहीं होती है इन दोनों मौसमों की बारिश फसल के लिए और किसानों के लिए संजीवनी बूटी का काम करती है, उन्हें यह अवश्य प्राप्त होनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि हमें ऐसी फसलों के बारे में सोचना चाहिए जो किसी भी प्रकार के क्लाइमेट को सहन कर सके। जिसमें बाढ़ को सहने की ताकत भी हो और सूखे को सहने की ताकत भी हो। किसानों को अगर अपनी लागत के बराबर भी फसल प्राप्त नहीं हो रही तो इसके बारे में कुछ न कुछ नया इजाद किया जाना चाहिए । आज साइंस इतनी तरक्की कर रही है, हमने कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान किए हैं, सरकार भी इस पर बहुत काम कर रही है, लेकिन ...(व्यवधान)।

श्री उपसभापति: आप कंक्लूड कीजिए।

डा॰ फागुनी राम: सर, मुझे अभी बोलने दिया जाए। मैंने अभी तो शुरू ही किया है और अभी तो मैं केवल किसान की ही बात कर रहा हूं, उसके बाद में मजदूर के विषय पर आऊंगा ... (व्यवधान)

श्री उपसभापति: 12 मिनट तक आपने सिर्फ किसान की ही बात की है?

डा॰ फागुनी राम: सर, अभी तो मैं बोल रहा हूं, मुझे आधे घंटे का समय दिया जाए।

श्री उपसभापति: नहीं आधा घंटा नहीं, दस मिनट ले लीजिए।

डा॰ फागुनी राम: कहते हैं कि जो शोध किया जाता है वह अनुसंधानशाला में किया जाता है, लेकिन हमें लैंड टू लैंड जाना चाहिए, लेबोरेटरी को जमीन के पास जाना चाहिए क्योंकि जमीन के पास जा कर ही वास्तविक रूप से वे बता सकते हैं कि कौन सी मिट्टी को कितना पानी चाहिए, कितनी खाद चाहिए, कितनी गर्मी चाहिए और कितनी आर्द्रता चाहिए। हमें कम समय में पैदा होने वाली फसलों की जानकारी होनी चाहिए ताकि किसान इसे जान सकें। इसके लिए वैज्ञानिकों को लैंड टू लैंड जाना चाहिए, ताकि वे किसानों को यह बता सकें कि इस पर्टिकुलर जमीन में कैसी फसल होगी, कौन सी फसल होगी, कितने दिनों में होगी। यह जानकारी उसके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि हमारे किसान कर्ज लेकर फसल उपजाते हैं और फसल हुई नहीं कि कर्ज देने वाला हो या सरकार हो, वे सिर पर सवार हो जाते हैं कि आप हमारा ऋण ब्याज के साथ चुकाइए। वह काफी अधिक ब्याज के ऊपर ऋण लेता है और यदि उसे वह न चुकाए तब तो ऋण से ज्यादा ब्याज ही बढ़ जाता है और चक्रवृद्धि ब्याज होते होते इतना अधिक हो जाता है कि फिर उसें चुकाने के लायक भी नहीं रहता। इस स्थिति में उसे अपनी उपज जल्दी ही बेचनी पड़ती है। ज्यों ही उसे पैदावार प्राप्त होती है, उसी समय उसे अपनी फसल को बेचना पड़ता है और अपनी गरज के कारण वह उसे बहुत ही कम दाम में या औने-पौने दाम में बेच देता है। हम यह चाहते हैं कि सरकार के द्वारा एक नीति बनाकर ऐसा सोचा जाना चाहिए और सरकार ऐसा सोच भी रही है कि किसानों का जो लागत खर्च हो, उस लागत खर्च के साथ-साथ उन्हें अपनी मेहनत-मजदूरी का मूल्य भी मिले और जब वह अपनी फसल को बेचे तो उसे नुकसान न उठाना पड़े। हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा चाहिए कि खेती में लगाई गई लागत प्राप्त करने के बाद और अपने कर्ज को चुकाने के बाद वह कुछ खा भी सके।

सर, ये सभी बातें मैंने किसानों के बारे में कही हैं और आपका आदेश है कि समय का ध्यान रखा जाए इसलिए मैं मजदूरों के बारे में बहुत कम शब्दों में बात करूंगा। सर, एक किसान अपनी

खेती करने के लिए बैल रखता है, ट्रैक्टर रखता है। सर, मजदूर अपनी खेती करने के लिए बैल रखते हैं और ट्रैक्टर रखते हैं। बैल रखने वाला चाहे मालिक हो, चाहे जो किसान होता है, वह सुबह चार बजे उठकर बैलों को दाना-पानी कर देता है, उनको खिलाते हैं जिससे उनका पूरा पेट भर जाए। लेकिन सुबह उठकर उस किसान का चरवाहा, किसान का हरवाहा-कृषक मजदूर जब खेत पर बैलों को लेकर जाता है तो वह भूखे पेट ही होता है, पता नहीं उसने रात को भी कुछ खाया होगा या नहीं, भगवान जाने। तो वह अपने प्रकृति के अनुकूल जेठ की दुपहरिया में, भादों की अंधरिया में और माघ में ठिठुरते जाड़े में जो बर्दाशत नहीं किया जाता है, वह बेचारा उस सबको बर्दाशत करता है और अपने पेट के लिए, देश के लिए काम करता रहता है, उठता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। वह मजदूर जिसके इशारे पर बैल चलाता है, खेत में काम करते हुए उसको अगर दस बज गया तो बहुत कम ही लोग हैं जो उससे पूछने जाते हैं कि अभी तूने कुछ खाया या नहीं, पानी पीया या नहीं। वह बेचारा टकटकी लगाए रहता है अपने बाल-बच्चों की तरफ कि वे उसके खाने के लिए कुछ लेकर आएंगे, सत्तू ही क्यों न हो, कोई भी खाने की चीज क्यों न हो जिससे वह पेट की ज्वाला शांत कर सके और अपने को प्रकृत्ति की मार से बचा सके। सर, मैं एक चीज प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक किसान बैल से खेत को जोतता है और सावन भादों के मौसम में चारों तरफ पानी भरा रहता है, उसी खेत को वह जोतता है तथा उसका पानी लाल हो जाता है या जैसी किरन होती है, वह काली हो जाती है। बैल वहीं पर अपना मल-मूत्र त्याग करते हैं, जिसमें वह खेनी खाता है, उसमें न जाने कितने लोगों ने विष्टा की होगी। इससे पहले कितने पक्षियों ने, पशुओं ने, जानवरों ने की होगी, लेकिन वह बेचारा कृषक मजदूर खेत से बाहर नहीं जाता है और वह उसी खेत के गन्दे पानी, अशुद्ध पानी को अपने हाथ से ऐसे ही चलाकर पानी पी लेता है। अब आप सोचिए कि उसके स्वास्थ्य के बारे में क्या होगा। हम जल मिशन के बारे में कहते हैं, हम कहते हैं कि सबको पीने का शुद्ध जल मिले। लेकिन उन किसानों के बारे में क्या होगा, उन कृषक मजदूरों के बारे में क्या होगा, उनके बारे में क्या होगा, जिनके इशारे पर ये बैल खेत में चलते हैं? इसलिए यह जरूरी है कि किसानों के साथ-साथ कृषक मजदूर को भी दिया जाए। मैं किसान मजदूर के बारे में कहता हूं जैसा कि मैंने कहा कि कृषि सीजनल है, यह 12 मास नहीं चलती। साल में दो फसलें होती हैं-एक रबी की फसल होती है, दूसरी खरीफ की फसल होती है। इन दो फसलों के अलावा साल में मुश्किल से तीन माह कृषि के कार्य में एंगेज रहते हैं। बाकी नौ महीना उनके पास कोई काम नहीं रहता है। आप जानते हैं कि किसानों, मजदूर के पास, कृषक मजदूरों के पास उनकी सारी पूंजी ही उनकी मेहनत है। उनको जिस दिन मजदूरी मिली जो वे खाते हैं और जिस दिन मजदूरी नहीं मिली तो वे बेचारे भूखे रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इन बचे हुए क्षणों में जिनकी मेहनत ही पूंजी है उन मेहनतकशों को मेहनत में कैसे लगाया जाए, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। हम समझते हैं कि इन क्षणों में पशु लगाया जाए, सरकार को

इस बारे में सोचना चाहिए। हम समझते है कि इन क्षणों में पशु पालन किया जा सकता है, कुकुट उत्पादन किया ता सकता है, फिशरीज का किया जा सकता है, डेरी का फार्म खोला जा सकता है, कोआपरेटिव खोला जा सकता है, बहु-मौसमी और बहु-फसली फसलों को ईजाद किया जा सकता है ताकि उन लोगों को साल भर काम मिलता रहे। इससे हमारे किसान भी संतुष्ट और हमारे कृषक मजदूर भी संतुष्ट होंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि फसल के बारे में, किसानों के बारे में और कृषक मजदूरों के बारे में हमें ध्यान देना चाहिए ताकि ये लोग भी सफल हो सकें। सरकार यह देश है और देश के किसान ही उसकी रीढ़ हैं और उसकी शक्ति हैं। किसान मजदूर और खेत में काम करने वाले बैल, क्योंकि मजदूर जो काम करता है वह बेचारा खुद करता है लेकिन वह अपने कंधों पर रखकर खेत जोत नहीं सकता। उसे बैल चाहिए जो कांधे पर रख करके जोत सके। बड़े लोगों को ट्रेक्टर चाहिए जो उसमें डीजल, पैट्रोल डालकर जोत सके, फिर उसको चलाने वाला चाहिए जो खेत को जोत सके। सर, ये बातें बड़ी विचारणीय हैं, बड़ी ह्यूमन बात है जिस पर विचार किया जाना चाहिए और सरकार को इस पर बहुत सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए कि अब किसान को दुखी रहने का नहीं है।

यह बड़ी कारूणिक बात है, बड़ी सिम्पेथैटिक बात है किसान और कृषक मजदूर राष्ट्र की धरोहर हैं। सबसे ज्यादा अगर कहीं एम्पलायमेंट है, तो वह खेतों में है, लोगों का झुकाव अभी भी खेतों में है। जम्मू-कश्मीर में या शिमला में ...(*समय की घंटी*)... या पंजाब में जो फसलें होती है, वे कैश क्रॉप होती है। ...(*समय की घंटी*)...

श्री उपसभापति: डा॰ फागुनी राम जी, आप अब समाप्त कीजिए।

डा॰ फागुनी राम: हम उन जगहों पर जायें, जहां फल नहीं होते हैं, वहां पर हम तरकारी कैसे उपजा सकते हैं, फल कैसे उपजा सकते हैं ,सब्जियां कैसे उपजा सकते हैं और फिर उन फलों को, सीजनल फलों को कैसे अच्छा बाजार दे सकते हैं? मेरा ख्याल है कि अगर गांव में किसानों को और मजदूरों के लिए अलग-अलग को-ओपरेटिव सोसायटीज बन जायें और को-आपरेटिव सोसायटीज बनाकर के इन लोगों को सुविधा दी जाये, सुविधा के अनुकूल इनको प्रोत्साहन दिया जाये, गाइडेंस दी जाये, तो हम समझते हैं कि इससे यह देश और भी तरक्की करेगा। हम अन्न के मामले में आत्म निर्भर ही नहीं होंगे, बल्कि हमारे यहां अन्न सरप्लस भी होगा और हम विदेशों को अन्न निर्यात कर सकते हैं। इससे किसान सुखी हो सकते हैं। हमारी आबादी 70 परसेंट किसानों पर निर्भर करती है और किसान मजदूरों पर निर्भर करते हैं, सरकारी इक्युपमेंट पर निर्भर करती है। आज 10 परसेंट खेती भी आधुनिक टैक्नालाजी के आधार पर नहीं चल रही है, पुराने तौर तरीकों

से ही खेती की जा रही है। ...(*समय की घंटी*)... खेती में आधुनिक टेक्नॉलाजी का उपयोग बढ़ना चाहिए जिससे कि अन्न का उत्पादन बढ़ सके, कृषि का उत्पादन बढ़ने से कृषक ऊपर उठ सकेगा। मैं समझता हूं कि तभी देश का यह सपना,

"सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भाग्भवेत्।"

पूरा हो सकेगा। मैं इसके साथ आपके आदेश का पालन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जयन्ती लाल बरोट (गुजरात): माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे गरीब किसानों के बारे में बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि देश को आजाद हुए पचास साल से ज्यादा हो गये हैं, लेकिन सरकार एक ही फैमिली की या एक ही पार्टी की बहुत सालों तक चली। जब-जब उनकी सरकार आती है, तब-तब गरीब की बातें होती हैं, किसान की होती है, दलित की होती है, आदिवासियों की होती हैं, लेकिन जब सरकार नीतियां बनाती है, तब बड़े लोगों को सुखी करने के लिए और गरीब गरीब ही रहे, ऐसी नीतियां बनती रहीं, इसीलिए किसान गरीब रहा, गरीब गरीब रहा, गरीब की संख्या किसान की संख्या गरीबी की ओर बढ़ती रही और बीपीएल वाले इसमें बढ़ते ही रहे। कृषक, मजदूरों के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं था, ऐसा भी मैं कह सकता हूं। आज किसान के लिए अगर सरकार चाहती है, तो एक उदाहरण मैं गुजरात का आपको दे सकता हूं। गुजरात सरकार ने किसानों के लिए जितने वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिकों का एक महीने तक पूरे गुजरात में दौरा करवाया। अठारह हजार गांवों में किसानों को इकट्ठा किया, कृषि में क्या-क्या नये-नये अनुसंधान हुये हैं, वैज्ञानिक पद्धति से कैसे खेती हो सकती है, इस तरह की सभी जानकारियां देने का एक प्रोग्राम बनाया था और 18 हजार गांवों में घूमने से गुजरात के किसानों को पहला फायदा क्या हुआ कि वर्ष 2002-2003 में सात हजार करोड़ रूपये का कृषि का उत्पादन हुआ था। गत साल में 25 हजार करोड़ का कृषि उत्पादन हुआ है, इसका सीधा फायदा किसानों को और किसान मजदूरों को हुआ है।

दूसरी बात यह है कि किसान को क्या चाहिए। किसान को खाद चाहिए, किसान को अच्छा बीज चाहिए, किसान को पानी चाहिए, किसान को बिजली चाहिए, किसान को जो भी चीज़ चाहिए, वह सरकार द्वारा दी जानी चाहिए, लेकिन वह नहीं मिली और किसान बिना पानी, बिना खाद, बिना बीज और बिना बिजली दुखी होता रहा है। सरकार को किसानों के लिए और भी छूट की व्यवस्था करनी चाहिए। जो छोटे किसान हैं, जो सीमांत किसान हैं, जो कृषक मजदूर हैं, उनके लिए सरकार और योजनाएं बनाये, जिससे उन्हें और रोजगार मिले। साल में 365 दिन होते हैं,

उनमें से 100 दिन रोजगार देने से काम नहीं चलेगा, जो बीपीएल वाला गरीब किसान मजदूर है, उसकी तरफ हम देखें तो वह क्या खायेगा? क्योंकि मंहगाई बढ़ती है, आमदनी कम होती है। मंहगाई और आमदनी के बीच में जो फासला है, उस तक किसान कभी पहुंच नहीं सकता है। इस कारण किसान अपने घर के बच्चे को भी काम में जोड़ता है, अपनी लड़कियों को काम में लगाता है, पशुधन को भी खेती में लगाता है, उसे पशुधन को भी सम्भालना पड़ता है, जिसके कारण उसके बच्चे पढ़ नहीं पाते है, उसकी लड़कियां भी पढ़ नहीं पाती हैं, न पढ़ने के कारण यह गरीबी और भी बढ़ती जाती है।

मैं मानता हूं कि उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए कुछ अच्छे इंतजाम किए जाएं और उनकी गरीबी दूर करने के लिए सरकार उन्हें बिना सूद के ज्यादा से ज्यादा लोन दे, जिससे किसान कृषि के काम के लिए बैल ला सके या उससे संबंधित औजार ला सके। अगर एक किसान को साल भर खेती करने के बाद हिसाब करने पर नुकसान होता है तो सरकार की ओर से उसे कुछ मुआवजा दिया जाए जिससे वह अपने कुटुम्ब को बचा सके और जो थोड़ी बहुत आमदनी है, उसके सहारे काम चला सके। मैं सरकार से विनती करूंगा और नारायणसामी जी के बिल का समर्थन करूंगा कि गरीब और कृषि मजदूर के लिए सरकार को और अच्छी योजनाएं बनानी चाहिए और पूरे देश के जो सीमांत मजदूर हैं, छोटे किसान हैं, कृषि मजदूर हैं, उनको खेती में अच्छी तरफ कैसे आमदनी बढ़ाई जाए, उसके लिए रास्ता दिखाना चाहिए तथा उन्हें पूरा मार्गदर्शन दिया जाए जिससे वे अपने कुटुम्ब को बचाने के लिए काम कर सके। नहीं तो उसके ऊपर जब बोझ पड़ता है तो उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। इस प्रकार का समय न आए, इसके लिए सरकार खास तौर पर राज्य सरकारों को भी बोले और केन्द्र सरकार की ओर से भी उनके लिए कुछ अच्छी योजनाएं बनें। इसी विनती के साथ मैं नारायणसामी जी के बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

डा. एस.एस. गिल (पंजाब): सर, मुझे कितना समय मिलेगा?

श्री उपसभापति: आधा घंटा।

डा. एम.एस. गिल: धन्यवाद उपसभापति महोदय, शुक्रवार को जुम्मा कहते हैं। मुझे, यह जुम्मे का जो दिन होता है, वह बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बाकी दिन तो झगड़ा होता रहता है कि कौन बोले और कौन न बोले, बोले भी तो कोई बोलने नहीं देता, सुनता तो कोई भी नहीं है लेकिन यह दिन अपना ही है, चाहे दो बैठे हों या दो सौ बैठे हों। जो आपने टी.वी. चैनल लगा दिया है, बड़ा अच्छा किया है, लेकिन उसका भी, इनफॉर्मेशन मिनिस्टर टीवी पर दिखाते हैं कि ये दिखाने पड़ेंगे, लेकिन एप्लीकेशन नहीं है, केबल वाले या दूसरे रोक देते हैं। फिर भी लोक सभा या राज्य

सभा को हिन्दुस्तान बहुत देख रहा है। इस प्रकार हम लोग यहां चाहे दस हों या बीस हों या कोई भी न हो, जब वे बोलेंगे तो कुछ न कुछ उन तक पहुंच ही जाता है और मुझे यह अच्छा लगता है।

सर, नारायणसामी जी के रेज़ोल्यूशन को मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा। पिछली दफा मैंने कहा था कि मैं इस पर बोलूंगा। जब मैंने इसे पढ़ा तो मैं सोचने लगा कि शायद मैंने ही इसे लिखा होगा और अगर मैंने नहीं लिखा जो उनके दिमाग में टेलीपेथिक मेरा ही ख्याल गया होगा क्योंकि हमारा दिल और दिमाग, लगता है कि किसान के मामले में एक ही है। यह सारा मैंने पढ़ लिया है कि क्या-क्या नुकते ये ला रहे हैं और मैं उन्हीं पर अब चर्चा करूंगा ये फिगर्स बहुत लम्बे हैं, मैं दोहराऊंगा नहीं कि 65-70 परसेंट आज भी दिल्ली से बाहर हैं, गांव में हैं - बंगलौर से भी बाहर हैं, जितनी मर्जी तारीफ करते रहो। यहां से दस मील रोहतक की तरफ चले जाओ या दो मील नोएडा से आगे चले जाओ तो असल हिन्दुस्तान - गांधी का और नेहरू का हिन्दुस्तान - आज भी वही हैं मैं तो देखता हूं इधर या उधर जाता ही रहता हूं। क्या कुछ हम लोगों ने उनके लिए आजादी के बाद किया, इस संबंध में खास कर मैं यह सोचता हूं कि पहले दस-पंद्रह साल तो, सच्ची बात यह है कि आजादी किसी हिसाब से कच्ची थी। आइज़न हावर का भेजा हुआ पीएल-480 आता था, जहाज आता था, लेबर को देते थे, प्राइसिज़ और ठंडक रहती थी, उससे हम ठंडे रहते थे। फिर इंदिरा गांधी जी के समय में 1966 में यह हुआ, मैं उसमें हिस्सेदार हूं, पंजाब में काम करता था और इसी सब्जैक्ट में किया है। फिर सुब्रहमण्यम जी ने एक जहाज मंगाया था बारलॉग-सीड कनक का, गंदम का। बाकी लोग सारे डरे कि ये बीजेंगे और न निकला तो मर जाएंगे। पंजाब सारा जहाज ले गया - मैंने किताब में लिखा हुआ है, पुरानी बातें हैं - और वह ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। इसमें मेरा ख्याल कोई exaggeration नहीं है, ग्रीन रेवोल्यूशन था और आज भी बदकिस्मती से essentially पंजाब रेवोल्यूशन ही है। आज भी 60 या 50 या 70 परसेंट राइस और वीट वहां से ही सरप्लस आता है, जिससे आप देश का सारा पीडीएस चलाते हैं। चलो ठीक है। हरेक ने अपना-अपना काम करना है। लेकिन उस वक्त पंजाब में भी खुशहाली आई। जो एम. एस.पी. दिया था, उससे इन्वेस्टमेंट हुई। सरकार ने भी बहुत इन्वेस्टमेंट की यह मानना होगा, हम लोगों ने पढ़ा है। इरिगेशन पर बहुत सी इन्वेस्टमेंट हुई। उसकी फिगर्स हैं, मेरे दोस्त वहां बैठे हैं, उनको तो याद होगा, पर मैं अन्दाजे से जानता हूं और उससे सारा कुछ हुआ, पंजाब की भी तरक्की हुई। तब हरियाणा और पंजाब एक ही थे। और लोगों की भी तरक्की हुई, लेकिन आज जो सिचुएशन है, जो नारायणसामी जी ने निकाली है, सब कह रहे हैं और हम पिछले दो-तीन दिन से किसी न किसी बहाने एग्रीकल्चर पर ही चर्चा कर रहे हैं।

[उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन) पीठासीन हुए]

तो उसकी बड़ी चिन्ता है, पहली तो यह है कि सारे फिगर्स हैं, कोई उन आंकड़ों को निकाल कर देख ले कि जो इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में है, वह पिछले दस-पन्द्रह सालों से बिलकुल कम

होती गई हैं । हिन्दुस्तानी बजट का एक बड़ा चुस्त तरीका है कि ऐलोकेशन्स दिखा देते हैं, तो आप सब लोग तालियां बजाते हैं, 28 को फिर बजाओगे। जो सिस्टम बना हुआ है ब्यूरोक्रेसी का, मैं भी उसमें रहा। अब से लेकर, अप्रैल से सितम्बर तक, वे कहते हैं कि इनडिविजुअल स्कीम एप्रूव करेंगे. उसमें ही घूमते रहते हैं। जब पैसा सेंक्शन होता है, किसी स्टेट को जाता है, तब दो महीने रह जाते हैं, आखिरी दिनों में कुछ खर्च करते हैं और बाकी तीस-चालीस पचास परसेंट बचा लेते हैं, from a limited allocation और आपका बजट भी बैलेंस हो जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर की तारीफ हो जाती है और किसान का भी भांडा फूट जाता है, सत्यानाश हो जाता है। यह सिचुएशन है।

इरिगेशन में तो बिलकुल stagnation है, इसके भी फिगर्स हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, दूसरा जो सिचुएशन आई है कि एक तरफ न तो व्हीट की नई टेक्नालॉजी है और न राइस की है। पंजाब एग्रीकल्चरल युनिवर्सिटी, में by the way, investment भी नहीं है। मैं जानता हूं, बहुत बारीकी से जानता हूं, Agriculture Universities सिर्फ जितना बजट पंजाब गवर्नमेंट देती है, तो वह सिर्फ तनख्वाहें ही चलती हैं। रिसर्च तो खत्म हो गई, बहुत ढीली हो गई और ICAR की भी मैं बड़ी कमी देखता हूं। इनवेस्टमेंट की भी और काम की भी - मैं जानता हूं, मैंने किया है, देखा हैं इसलिए इंडिया में रिसर्च नहीं होती, बहुत कम होती है। दूसरी तरफ WTO भी साथ ही आ गया। राजीव गांधी जी के समय में मैं सेक्रेटरी बना था, वी.पी. सिंह के साथ और वह सारा समय मैंने देखा है उस वक्त मैं पेट्रो-केमिकल्स में था, फार्मास्युटिकल्स जिसके ऊपर अमेरिका से झगड़ा है, मैं उस मीटिंग में जाया करता था। आहिस्ता-आहिस्ता, मैं देखता था कि उसमें साइन तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। हमारे साथ जो ग्रुप थे, वे आहिस्ता-आहिस्ता खिसक गए, Punta del Este और फिर सबने किया, और इधर भी हो गया। लेकिन अब जो स्थिति है, हांग-हांग का भी मैंने देखा, तो ठीक है थोड़ी-थोड़ी तरक्की दिखाते हैं, इतनी तरक्की दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि पंद्रह साल को फिर सोच लेंगे, आप बारीकी में जानते हैं और reality यह है कि हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो barrier थे टैक्सेशन वगैरह के, इंपोर्ट ड्यूटीज के, वे तो अब गिराने पड़ेंगे। उन्होंने तोड़ दिए हैं और तोड़ रहे हैं। और कोई चारा नहीं हैं अगर है तो मुझे समझाइए। अमेरिका के फार्म मैंने देखे हैं, जो 10,000 हैक्टेयर का फार्म है, उसके साथ यहां दो एकड़ वाला कैसे करेगा? आबादी तीस करोड़ से सौ करोड़ हो गई है, आजादी के बाद से अब तक, तीन गुना हो गई है। हमारे जो छः-छः एकड़ थे, अब एक-एक एकड़ ही रह गए हैं या पौना-पौना एकड़ रह गया है, यह हर स्टेट की स्थिति है। पंजाब का भी यही हाल है, जाकर देखो तो सही। गरीबी सारे हिन्दुस्तान में है, परन्तु पंजाब में, मेरे गांव में जो गरीबी है, मुझे उसे देखकर रोना आता है, क्योंकि मैं वहां रहा हूं, मैंने देखा है। इस हालत में अब तो व्हीट भी आ सकता है, राइस भी आ सकता है। अभी दो दिनों से हम यही चर्चा कर रहे हैं, कि चार-पांच लाख टन व्हीट

आएगा, तो क्या बनेगा? उसका मार्केट में क्या असर पड़ेगा? मध्य प्रदेश का व्हीट – ग्वालियर का, शिवपुरी का कट रहा है, पांच-सात दिन में कटना है, नैचुरली वहां से गरमी आती हैं पंजाब का भी तीन हफ्ते में कटना शुरू हो जाएगा, तो वह कहां जाएगा, the recent atmosphere in trade, everybody know it. अगर कोई व्हीट आ रहा है, चाहे मद्रास में ही आप उसको स्टोर कर लेंगे, लेकिन माफ करना जो ट्रेडर है, असर तो उसका अमृतसर में पड़ेगा और हर जगह पड़ेगा। यह कहना कि नहीं पड़ेगा, मैं नहीं मान सकता। वह भी आ रहा है।

हिमाचल के जो apple थे और कश्मीर के जो थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से apple आते हैं। खान मार्केट में हम लोग जाते हैं, तो हमको कोई देसी सब्जी या फ्रूट लेने नहीं देता। अगर मांगें तो वे कहते हैं कि आप कहीं और जाओ। फिर हम जाते हैं गांव की मंडियों में। ...(*Interruptions*)...Sir, Smt. Sukhbans Kaur is confirming what my wife also does everyday. क्योंकि वहां तो गोरे आते हैं खान मार्केट में! उनको ही वे बेचते हैं। हमारे अपने ही जो हिन्दुस्तानी भाई हैं, वे हमें पहचानते नहीं हैं वे कहते हैं कि जाहो-जाओ, कोई नहीं, आप कहीं और से ले लो। एप्पल इम्पोर्टेड ही लेना पड़ता है तो, यह दशा है, इसका मुकाबला कैसे मुकाबला होगा? अब ठीक है, जोर लगता रहता है, कोशिश होती रहती है, मुझे नहीं दिखता कि हमें उसमें कितनी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि मजबूरियां हैं। मैं पंजाबी में बोलता हूं कि यह दुनिया 'तगड़े' की और 'माड़े' की है, the strong and the weak. (**व्यवधान**)... लेकिन दुनिया ताकतवर और कमजोर की है, ऐसा ही है। इसमें यह सब कुछ दिख रहा है। अब इस साल मैं देख रहा हूं कि हम ये बातें क्यों कर रहे हैं? एक तरफ तो दिसम्बर-जनवरी में पहली बारिश और snow in the hills of the north आना होता है। इससे मध्य प्रदेश तक बारिश का फायदा होता है। मैं जानता हूं यह फायदा सारे नॉर्थ इंडिया से लेकर सैन्ट्रल इंडिया का होता है। फरवरी के जो ये दिन हैं, सैकंड एंड थर्ड वीक, इसमें सैकंड बारिश का होना होता है। अगर यह हो जाए जो राजस्थान हरियाणा और सारे नॉर्थ का बाजरा और ये ऑयल सीड्स सब पैदा हो जाते हैं। पंजाब को भी पानी चाहिए क्योंकि ट्यूबवैल से यह सब नहीं हो सकता है। ट्यूबवैल के कुल 120 ब्लॉक्स हैं, जिनमें से 117 तो ग्रे हो गए हैं। हम भी डीप ट्यूबवैल लगा रहे हैं। जब हम ऐसे ही पानी निकालते थे अब वे दिन गए। आप सोचते हैं कि पंजाब वाले इरिगेशन में ज्यादती करते हैं, सच्चाई को कभी कोई देख ले, या पूछ ले, It is a little more than what the reality is. इसलिए हमको भी बारिश चाहिए। अब इस साल बारिश नहीं हुई, अभी बहुत ऊंची गर्मी आ गई है, तभी तो हम ऐसे बैठे हैं, नहीं तो यह फरवरी का महीना है। इसका मतलब हैं, wheat grain shrivel होगा। वह मोटा नहीं बन सकता है क्योंकि उसको ठंडक चाहिए। अब सरसों में भी aphid और कीड़े लग गए हैं, तो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और यूपी, सब की जाएगी। इसके साथ ही कनक की मार्केट भी जाएगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हिन्दुस्तान का

किसान बड़ी दिक्कत में हैं। मैंने कई दफा यहां पर आन्ध्र प्रदेश में हो रहे सूइसाइड्स के ऊपर बात की है? क्योंकि सारा आन्ध्र प्रदेश पत्थर का प्रदेश है। एक तरफ तो पंजाब और हरियाणा का जो क्षेत्र है, इसमें थोड़ी सी जमीन है और दूसरी तरफ जो गंगा का क्षेत्र है, वहां से लेकर बंगाल तक का जो क्षेत्र है, उसमें है बाकी तो सारा एरिया plateau है और ये plateau volcanic है, तो उसमें बड़ी मुसीबत है और इसलिए विदर्भ का चक्कर है। उनकी जो कॉटन की कहानी है, वह अखबार में आती रही है और मैंने उसे पढ़ा है हम जानते हैं और मानोक्रोपिंग से हम उनको कमर्शियल पर ले गए। पंजाब में भटिंडा जो कॉटन किंग था वहां पर हर रोज सूइसाइड्स हो रहे हैं। मैं पंजाबी अखबार पढ़ता हूं और मैं सभी मंत्रियों से एक अर्ज करना चाहूंगा कि आप vernacular अखबार पढ़े। आप तमिल, हिन्दी और पंजाबी, जो मर्जी अखबार पढ़े, लेकिन आपको खबर वहीं से ही मिलेगी, अंग्रेजी के अखबार से नहीं मिलेगी। अंग्रेज तो मैं भी हूं, लेकिन वह बात अलेहदा है। मेरी वह दुनिया अलेहदा है, उसका इससे, हिन्दुस्तान से कोई संबंध नहीं है। आपको यह कभी पता नहीं लगेगा कि देश क्या सोच रहा है। मैं इलैक्शन के टाइम में हमेशा vernacular प्रैस को ही पढ़ता था या पढ़ाता था कि बताओ वहां क्या हो रहा है और लोग क्या कह रहे हैं, तो कुछ पता लगता था। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी मध्य प्रदेश तथा और भी आगे तक जो अब इस सीजन में यह गंभीर मसला आया है, यह बिल्कुल ठीक है एक तरफ जो wheat आ रही है, उसका ग्रेन नहीं बनेगा और दूसरी तरफ ऑयल सीड गिर रहा है। जब यहां पर सुबह पोटेटो की बात पर जवाब दिया तो मैं उस पर बात नहीं कर सका। हमें frost भी मार गई और बर्फ न पड़ना व बारिश का न होना भी मार गया। हमारा पोटेटो का 70 हजार हैक्टेयर forst से खराब हुआ है। अकेले पंजाब का 50 हजार हैक्टेयर है, ये फिगर्स शरद जी के हैं। जो उन्होंने हमें दिए हैं। इसके अलावा बाकी यूपी और आस-पास का है। इसका जवाब क्या है? जवाब यह है कि एक तो यह डिजास्टर में नहीं आता। अगर आप गर्मी से मरोगे तो आपका इलाज करेंगे यदि ठंड से मरोगे तो मर जाओगे। यह तो बड़ी illogical चीज़ है, लेकिन यह उन्होंने पढ़कर सुनाया। कैबिनट को या कंट्री को क्या मुसीबत है कि वह एकदम कर दे कि डिजॉस्टर तो डिजॉस्टर ही है, अगर कुछ करना है तो। दूसरा जवाब आया कि पंजाब और यूपी ने भी लिखकर भेजा है। अगर वे ढीले हैं तो आप तो देश को देखते हैं, इसलिए मालिक तो आप हैं, तो यह हालत आलू और दूसरी चीजों की हो रही है। यह मुसीबत इस सिलसिले में बहुत गंभीर है, जो ये किसान को कहते हैं कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है और इधर-उधर सूइसाइड्स बेअंत हो रहे हैं, मैं कभी नहीं भूलता। कई साल पहले मैंने एक न्यूज़ चैनल पर देखा था, टी०वी० पर आंध्र प्रदेश की खबर आ रहीं थी, एक मां के तीन बच्चे खड़े थे, उस मां की एक लड़की थी 8-10 साल की, वह मां कहती थी ''मैंने इसको दे देना है'', You know what it means. ''मैं इसे पाल नहीं सकती, मैं छोटे बच्चों को पालूंगी''। यह देखकर मेरा दिल कांप गया, और आज भी यह सोचकर कांपता है कि यह हो रहा है। How can I think of it? I have also got three daughters. But the mother said, "I am giving her. I cannot look after her." We have

read of Karnataka कि वे छोटे बच्चों को 500 रुपए में बेच देती हैं, यह रोज हो रहा है, क्या-क्या हो रहा है, रोज खबर आती है। साहिर लुधियानवी, मेरे ही कॉलेज के, लुधियाना के बहुत बड़े कवि थे, अब वे नहीं हैं, उन्होंने 1958 में ''परछाइयां'' पोयम लिखी थी, यह काफी लंबी पोयम है, लेकिन इसकी दो-तीन लाइनें मुझे याद हा जाती हैं—

''हल बैल बिके खलिहान बिके,
जीने ही के हाथों जीने ही के सामान बिके।
जब कुछ भी न रहा बिकने को,
जिस्मों की तिजारत होने लगी।''

I hope you all understand. This is a condition I see here and there and this is the farmer's condition. That is what you have to, somehow, address. Shri Narayanasamy has written this कि इसका कुछ करो अब पंजाब में जितना Green Revolution हुआ, मैं उसका हिस्सेदार हूं, मैंने कैम्ब्रिज जाकर इस पर किताब लिखी, उस समय कोऑपरेटिव बैंकों और रिज़र्व बैंक के माध्यम से हमने 60-70 परसेंट लॉग टर्म, मीडियम टर्म, क्रेडिट दिया था, It was a great achievement of India and ours also because we did it properly. We used to recover 80 to 90 per cent. आज पंजाब में 9 लाख ट्यूबवैल हैं, जब कि पंजाब का एरिया है सिर्फ 50,000 किलामीटर का, जो यू.पी. के दो जिलों में समा जाए, बाकी किसी स्टेट में देख लो, एक लाख ट्यूबवैल होंगे या इससे कम होंगे। वे सारे ट्यूबवैल हमने मीडियम टर्म से लगाए थे, क्रॉप लोन से लगाए थे, लेकिन आज पंजाब में कोऑपरेटिव बैंकों का क्रेडिट 20 परसेंट है, बाकी साहूकार व्यवस्था वापस आ गई है। लॉर्ड कर्जन के समय 1850 में जो व्यवस्था थी, मद्रास में भी थी, यहां भी थी, वहां भी थी। इसीलिए उन्होंने उस समय कोऑपरेटिव बनाया था, 1904 का ऐक्ट और 1912 का ऐक्ट इसीलिए बनाया था, लेकिन अब वह खत्म हो चुकी है। अब बात आती है कि क्रेडिट इन्होंने बढ़ा दिया है, जरूर बढ़ाया है, लेकिन वह किसान जिसको इन्होंने क्रेडिट देना है, चाहे वह छोटा किसान है, या कोई भी है, वह actual cultivator तक नहीं पहुंचेगा, because he is not eligible for the credit. How do you make him eligible? उसके overdues हो गए हैं।

महोदय, एक चीज पर मुझे बहुत दुःख हो रहा है। मैं रोज पंजाब में भी कहता हूं, यहां भी कहता हूं — 1935 Unionist Government, Sir Chhotu Ram — ठीक है कि अंग्रेज लोग imperialist थे, सारा बुरा काम कर गए, लेकिन अगर कोई राज करे तो कुछ अच्छा भी कर ही जाता है, क्योंकि उसको जनता को ठंडा रखना होता है, चलो यही objective सही। उस वक्त जब पंजाब में साहूकार व्यवस्था थी, तो उन्होंने Debt Conciliation Board बनाए थे।

अफसर बैठते थे, साहूकार को बुलाते थे, अनपढ़ किसानों को बुलाते थे और पूछते थे- ''कितना कर्ज दिया - दस हजार, कितना सूद चढ़ा - एक लाख, एक लाख कैसे चढ़ गया? Cancelled जो भी हो, I am just giving exaggerated figures. But it is happening today It is 45 per cent in Punjab and elsewhere क्योंकि आढ़तिया तो अपने हिसाब से कर्ज देगा, अगर लेना है तो लो, मजबूरी में वे लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का क्रेडिट कम हो गया है। तो उसमें वे write-off करते थे, वे कहते थे कि यह किसान 20 किश्तों में कर्ज वापस देगा और उसके जीने के साधानों की कुर्की आप नहीं कर सकते, You cannot take away from him. This is very fundamental. But today's laws have changed it. I think the laws were changed to help the banks to recover the overdues. लेकिन जो ढ़ाई लाख करोड़ non-performing assets हैं, उस दिन भी फाइनेंस मिनिस्टर बोल गए, उनको तो कोई recover नहीं करता, औरंगजेब रोड की कोठी तो कोई लेगा नहीं, लेकिन किसान की जमीन ली जा रही है। रोज खबरें आ रही हैं कि 10 एकड़ वाले, 15 एकड़ वाले किसान की जमीन ली जा रही है। मैं आपको यह पंजाबी का आंकड़ा बांट देता हूं, आप सब लोग इसकी फोटोकॉपी करवा लें, इसको पढ़वा लें। It is very serious. This will lead to a serious social problem in our country. We can see what is happening from Napal to Karnataka. That is the problem. We have to deal with the farmer's impossible condition of credit and overdues and exploitation by those who give him money. That is all I have to say.

उपसभापति जी, मैं crop insurance के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। जब मैं Development Commissioner था, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की crop insurance refuse कर दी थी, क्योंकि फिर वही चीज होती है, वह ऐसे तरीके से बनती है कि आप इतना दोगे। जैसे कोई भी करता है, तो आप प्रीमियम बहुत बढ़ा देंगे, चाहे वह छोटा या कैसा भी किसान हो और जब आपको कंपेंसेशन देनी है, तो वे कहते हैं कि हम तो एवरेज लेंगे, तहसील का या जिले का। You are never eligible. मैंने उस वक्त पंजाब में करवाया था, शायद यह अब भी चलता होगा, मैंने कहा कि चलो जी, यह तो हम नहीं करेंगे, नहीं कराओ, शायद मैंने आज भी कहीं पढ़ा कि हम उसमें नहीं हैं। जिस इंश्योरेंस की तारीफ की जाती है, उसे बारीकी से पढ़कर आप देख लेना, मुझे जो शक है, वह आज भी यही है। हमने यह किया था कि हमारे यहां अप्रैल में ठंडक आई थी, अब अप्रैल में हेल-स्टॉर्म आएगी। जो कटने वाली कनक हैं, इसमें ऑन एवरेज 40 हजार हेक्टेयर तबाह होगी, पंजाब की और ऐसी ही हरियाणा की भी। मैंने कहा कि मि॰ गर्वनर, जिसकी पूरी तबाह हो जाए, "Just give me Rs. 2,000 an acre at least", and he paid promptly. 10-20 करोड़। हमने अपने यहां इतना तो कर दिया, शायद आज भी चलता होगा। अगर आपकी इंश्योरेंस इफेक्टिव नहीं है, effective in payment not in premium,

तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसके ऊपर मैं आपको इतना ही कॉशन करना चाहता हूं।

मैंने डिसास्टर फंड की बात की थी कि इसमें ठंडक तो आती नहीं है, गर्मी करो तो आपका बचाव करेंगे, तो यह बात मेरे को समझ में नहीं आई।

आजकल एक और नई चीज हो रही है, पंजाब में भी हो रही है, वह है कांट्रैक्ट फार्मिंग। In other words, we are all going in for big commercial farming. जो छोटे किसान हैं या कोई गाँव के जो लोग हैं, उन्हें तो इसमें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। जो कांट्रैक्ट फार्मिंग है, उसके ऊपर मैं आपको एक ही शब्द कह देता हूँ। अगर आप शेर और बकरी की एग्रीमेंट कर दोगे, तो क्या बनेगा ! उपसभाध्यक्ष जी, बताइए, क्या बनेगा ! शेर तो बकरी को खाएगा ही। बकरी तो शेर को नहीं खा सकती। मैं अब यह पढ़ रहा हूँ कि जब हमें फसल की जरूरत नहीं है, तो जैसे पंजाबी में कहते हैं कि तेरे साथ मैं नहीं रहूँगी, क्योंकि तेरी दाढ़ी हिलती है, जब तू खाना खाता है। वो ना कर देते हैं, तो वह छोड़कर चली जाती है। दाढ़ी हिलती है, जब मैं खाना खाता हूँ। This is a serious fault, and I know it. मेरे को तो कई दफा ऐसा धक्का लगता हूँ। ...(व्यवधान)...नहीं, फिर मै हाथ जोड़कर उन्हें वापस ले आया। वे चले जाते हैं, फिर ले आता हूँ हाथ जोड़ देता हूँ। कई तरीके हैं। वे हमें आते हैं। ये जो कांट्रैक्ट फार्मिंग है, मेरे को वह आम हिन्दुस्तानी किसान को तो दिख नहीं रही है। मुझे यह नहीं समझ आ रही है कि इसका क्या बनेगा।

मैं इरिगेशन की बात करना चाहता हूँ, जो मैंने उस दिन थोड़ी-सी कही थी, लेकिन आज कुछ ज्यादा कहना चाहता हूँ। एक तरफ तो इंवेस्टमेंट नहीं हुई। ये फिगर्स तो सब जानते हैं, इधर के उधर के, कि 10-15 साल से somehow गवर्नमेंट इंवेस्टमेंट स्टैगनेंट हो गई, इसलिए इरिगेशन का चक्कर है। एक तो वह सारे देश में होनी चाहिए, जैसे-जैसे जिधर हो सकता है, उसे करना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि जो खेती है, उसके लिए तीन ही चीजें चाहिए- जमीन चाहिए, सूरज चाहिए और पानी चाहिए। चौथी कोई चीज नहीं। हमारे पास जमीन हैं, बीज वगैरह तो आप डालेंगे ही, लेकिन नेचर की जो चीजें हैं। वे तीन चाहिए। जमीन हमारे पास है, बहुत अच्छी है, जितने variation, variety of climate and soil इंडिया के पास हैं, दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसलिए अब हम स्ट्राबेरी भी लगा रहे हैं। I used to see कि गवर्नर की कोठी में ऊपर मशोबरा में हम थोड़ी-सी पुरानी, जिसे अंग्रेज बो गए थे, वह खाया करते थे, जब हम गवर्नर के साथ जाते थे। अब हम अमृतसर में कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं। मैंने डोबाई में रेत में देखी कि वे सारी फसलें होती हैं। पानी चाहिए और सूरज चाहिए। We are a tropical country. We have plenty of sunlight. Some people are lacking Sun. I say, about the Sun, that was are the Arabs of this century.तेल कभी

खत्म होगा, तो सूरज जब आएगा, तो हमारे पास है। इसलिए अगर वे नन-कंवेंशनल इनर्जी के ऊपर काम करते रहे, तो बहुत कुछ निकालेंगे, not just atomic. पानी का बन्दोबस्त तो करना ही है, पानी के बगैर यह नहीं होती, तो उसका उपाय करिए। जो मिसयूज़ हो रहा है और जो टेक्नोलॉजी चाहिए, चाहे पंजाब में ग्रे हो गया, ग्रेन के लिए हम ओवरयूज़ करते हैं। मैंने एक दफा युनिवर्सिटी में कहा था कि पंजाब एक बहुत बड़ा महान खेती प्रधान स्टेट नहीं है, मैं कहता हूँ। यह तो सिर्फ ग्रेन पैदा करने की, अनाज पैदा करने की एक फैक्ट्री है। मैंने उनको कह दिया था कि याद रखना एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी, लुधियाना कि फैक्ट्री का लॉक-आऊट हो जाता है, तो आपका होने वाला है। यह मैंने 6 साल पहले कहा था, आज उनका लॉक-आऊट हो रहा है। क्योंकि जब 60 मिलियन टन ग्रेन सरप्लस हो गया था, तब हमको धक्का पड़ता था, अब कहते हैं कि फिर डट कर करो। यह मैंने कई दफा देखा हुआ है कि यहां से हमें कहते हैं, "नहीं, नहीं, we can't procure; we don't need". Or FCI is told to go slow. And then, we don't know what to do! So, effective and sensible use of water: yes. All the technologies have to be used. One thing; on this business of river-thinking, I have to say what I understand, that a casual slogan either by our highest court or by anyone else, and I have read everyone who said something, that link up all the rivers immediately, tell us the progress that you are making in four lakh or five lakh crores; doesn't matter whether you have it or not". यह बात मुझे समझ नहीं आ रही है। यह बहुत गंभीर, टैक्नीकल मामला है। जो 1950 में डैम्स के बारे में सोचते थे, लेकिन आज दुनिया और हमारी व बाहर की साइंस व टैक्नालॉजी कुछ और सोचती है। इस के मेरी नजर में दो पहलू हैं। एक तो यह काम एक्जीक्यूटिव को करने हैं। हिंदुस्तान में जो भी सरकार बनाएं, पार्लियामेंट को जवाबदेही दें क्योंकि पॉलिसी वह बनाएगी। मैं तो ऐसा मानता हूं, अपनी डेमोक्रेसी को और कोई है ही नहीं। अब मुझे समझ नहीं आता कि और कोई रास्ता कैसे हो सकता है क्योंकि काहे के लिए हम कैबिनेट और प्रधान मंत्री की गवर्नमेंट बनाते हैं? पॉलिसी के लिए और पॉलिसी बनाने में उनको सारे देश और दुनिया की व हरेक की सोच लेनी है, साइंस लेनी है, अक्ल की हिस्सेदारी डालनी है और फिर उसे करो। जो जुड़ना चाहिए, उनको जोड़ो, लेकिन एक ब्लाइंड ऐसा देश और ऐसी चीज मेरी समझ नहीं आती। इसीलिए मैं बारीकी मैं पढ़ता रहता हूं। अभी केन-बेतवा का मध्य प्रदेश व यू॰पी॰ में हो रहा है। मैं उसकी चर्चा भी पड़ता हूं। आप बारीकी से पढ़ना चाहें तो किसी-न-किसी अखबार में सीरियस बात आ जाती है। तो वहां बेतवा की और उस की रिवर वैलीज हैं और मैंने बेतवा को देखा है। यह उन के लोगों की चिंता है कि यह करने की जरूरत है। उन की चिंता है कि इस का एडवर्स इफैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ेगा? पाकिस्तान में भी जनरल मुशर्रफ कर रहे हैं कि एक और डैम बनाएंगे। ठीक है, मैं समझता हूं, उन को क्यों जरूरत है। लेकिन बाकी जो लोग हैं, वे उसकी बहुत चिंता और चर्चा कर रहे हैं। डाउन स्ट्रीम में जो

सिंध वैली हैं, वे भी चिंता कर रहे हैं क्योंकि अंग्रेजों के समय में डाउन स्ट्रीम वैली का इंदुस रिवर का जो भाखड़ा प्लान शुरू हुआ था, तो उस वक्त का पंजाब चाहता था, लेकिन सिंध का एतराज था। Even under a British Government—we have read the history; we have read the books—that was all a matter of negotiation. There are downstream, riparian rights and upstream, etc., etc. इस वैली की, इस दरिया की, you cannot roll them over the national merely because you think it is a good idea. And if it is a bad idea, you do not have to pay for it and then the country pays for ever. Once you cement this country, you can't undo the cement. This is all I have to say. Yes, increase irrigation. There is a question of big dam; there is a question of small dam; and there is a question of other ways, whatever they are; but the Executive should decide after full consultations with everybody, पार्लियामेंट भी, अपोजीशन भी, कोई भी हो जो कुछ बता सकता है, बताना चाहिए। मैं तो ऐसा ही जानता हूं। That is the way I look at things. And then, certainly, you do it.

I think I should conclude, Sir. I don't want to waste the time of the House. There are other things. I think at the moment, I have said all the things I had to say. इसीलिए पंजाब में कहते हैं कि जितना मर्जी बोल लें, आप बातों में से बात निकालते रहेंगे। मैं वह नहीं करूंगा। मुझे आखिर में इतना ही कहना है कि किसान को भी कुछ स्पेस दो। एक बात और कहूंगा कि बजट 28 तारीख को आएगा। जब डा॰ मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस वक्त भी बजट बना था, 5 बने थे और मैं उस वक्त एग्रीकल्चर सेक्रेटरी था। तो मैं जबसे इस काम में आया हूं, सदा से देख रहा हूं कि ही साल जब बजट बनता है तो बड़ी विजिबल और बड़ी पब्लिसिटी के साथ मीटिंग्स होती हैं। मैं इंडस्ट्री का भी सेक्रेटरी रहा हूं चार साल, पेट्रोकैमिकल, कैमिकल और फॉर्म्युसिटिकल में भी रहा हूं, इसीलिए मुझे उधर का भी पता है। मेरा रिश्ता है, आज भी लोगों से प्रेम है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के लोग बैठे हैं वे जानते हैं। Well, I believe, that is our way to work. That is all. But whatever it is, एक बात, मुझे बड़ी अजीब लगती थी कि हर साल..... इस साल भी मैंने देखा कि इंडस्ट्री के साथ मीटिंग होती हैं, जो जरूर होनी चाहिए। Even within industry, you know, the big boys come. I would like to see a meeting even within industry with new rising stars like Yuvraj Singh, like Dhoni in the 30 to 40 age group of industrialists. वह मैंने कभी नहीं देखी। with anyone उधर के भी मैंने देखे, इधर के भी देखता हूं। बड़ी देर से देख रहा हूं। लेकिन, एक बात का मुझे जरूर एतराज़ हुआ और मैंने डा॰ साहब को टेलीफोन किया और कहा कि सर, यह बजट तो हिन्दुस्तान का बनना है, तो किसानों से कोई बात नहीं करनी है? ये जो 65 परसेंट लोग घूम रहे हैं, उनका कोई कुछ भी सुन

लो। He was good enough to invite me straightway, and, I, then, made an effort. मैंने सारे देश से 12 किसान चुने। मैंने कहा कि कोई 70 साल का नहीं होगा। Again, they will be active people, जो बोल सकते हों, वे अपनी प्रॉब्लम दे सकते हों। दो उधर के होंगे और दो इधर के होंगे। कोई रबर की तरफ से होगा, कोई जूट की तरफ से होगा, कोई व्हीट की तरफ से होगा, कोई ड्राई का होगा और कोई इरिगेशन का होगा। इस तरह मैं 12 आदमियों को लेकर गया। सुबह से दो बजे तक हम बैठे। वे लोग डटकर के बोले। मैंने उनको तैयार किया था। उन्होंने बड़े प्रेम से सुना। आखिर में कहने लगे कि क्या आपको भी कुछ कहना है? तो मैंने कहा कि यस सर। जाखड़ जी हमारे मिनिस्टर थे। मैंने कहा हाँ जी, मुझे कहना हैं। मैंने कहा कि मुझे इतना ही कहना है कि जो भी इन्होंने कहा, हमारी मिनिस्ट्री उसकी एन्डोर्समेंट करती है। I had not taken Mr. Jakhar's permission, but I thought he will be okay. दूसरी मैंने कहा कि Sir, for the last two years, you have been India's Minister for Industry. Would you like, would you please be India's Minister for Agriculture this Year? In other words, focus on agriculture, invest in agriculture, listen to agriculture, think about agriculture because with any system of development, वह लिबरलाइजेशन हो या कल का हो, we will not get where we claim we are going to get without the 65 per cent of India which is out there, and India which has to be carried, and you cannot carry him, if you do not give him the wherewithal to carry himself. Frankly, that is all he needs . He does not need any other kind of help. But, he also must get the consideration of the Government, must get the investment, must get the support, whether it is marketing, whether it is credit to the *aam aadmi,* whether it is then the ways to look after his crops, fruits, vegetables, technology. मैं अमृतसर के एयरपोर्ट के लिए क्यों शोर करता हूं। मेरा ड्रीम तीस साल से शुरु हुआ है। We have the nearest well-watered piece of land in the Punjab. We can grow anything fruits, vegetables, broccoli *west ki, east ki.* You know that. पीछे हमारे फ्रूट वाले हिमाचल के बैठे हैं। वहां बैठे हैं। And, they have the dollars two hours away in the Gulf. I am, of course,wanting to give comfort to Punjab people to come. Why should they rot in Delhi? They should land in their State, as everybody else is landing. But, I want even more than that. That, I believe, Punjab's *gobhi* and *gajar,* वह जो सुबह 5 बजे उखाड़ोगे, मैं 6 बजे जहाज से कारगो लाऊंगा और 8 बजे या 10 बजे कुवैत की मार्केट में ताजी रख दूंगा। हमारा जो फ्लेवर है, जो हमारी क्रॉप है, वह किसी के पास नहीं है। वे जो अपनी बीवियों के लिए फूल लेते हैं, वे हॉलैंड से नहीं आने चाहिए। वे यहां से जाने चाहिए। आपको पता ही है कि सारा ही देश यह कर रहा है। और मीट एण्ड पॉल्ट्री, चलो

यह मुर्गे का तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। हम इतनी जल्दी मर नहीं जाएंगे। वह तो हो ही जाएगा। इस प्रकार उनको जो भी चाहिए, चाहे बकरी का चाहिए या चाहे कोई और मीट चाहिए, यहां से जाएगा। इस प्रकार मेरा यह सपना है कि किसान को टेक्नोलॉजी दो, साधन दो,उसको चीप क्रेडिट दो और अगर आप दे देंगे तो फिर वह आपको दिखाएगा कि हम क्या कर सकते हैं। एक दफा, long ago, 70s में हमने कैलकुलेशन की थी कि जो पंजाब की, व्हीट एण्ड राइस की उपज है, और वह दुनिया में कोई ग्रेट नहीं है। वो तो "अंधों में काना प्रधान" हम कहते हैं। We look god here, but we are not good in the world.There are people who do far more than us .....(*Interruptions*)..... I am winding up, Sir. अगर वही एवरेज बिहार, यूपी में और बंगाल तक हो जाए and that land is better than us. हमारे पास तो पानी है, लेकिन उनके पास तो गंगा जल है और वहां तो कमाल की जमीन है, ऐसे करो तो सब कुछ निकलता है। अगर लेह कर लें तो उस वक्त हमारी प्रोडक्शन 100 मिलियन थी and we calculated कि वह 300 मिलियन होगी और अमेरिका नहीं, हिन्दुस्तान वर्ल्ड का ग्रेन पावर होगा। यह आज भी हो सकता है। इसलिए उसकी मदद कीजिए, उसका ख्याल कीजिए। धन्यवाद।

DR. GYAN PRAKASH PILANIA (Rajasthan): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for your kind indulgence. Dr. M.S. Gill has most eloquently, passionately and rationally put forth the plight of the Indian kisan and nobody would have, I think, pointed out more relevant factors which would somehow ameliorate the plight of the kisan if the Government follows them. I will take a very little time of this august House in putting forth what I feel is most horrendous, most pitiable plight of the farmer. It will be a tale of woes. He is born indebt, he lives indebt and he dies in debt; he is born in misrey, lives in misery and dies in misery. It may appear exaggerated, but this is the state of affairs. Otherwise, nobody commits suicide. Suicide not only in one State but in so many States it is there. When we look at those figures, we get shudder. I have certain figures, which I will just read out with your kind permission. Firstly, I will take Vidarbha These are the figures, which have come in the newwpapers properly fortified by arguments and data. I am only on Vidarbha. In 2002, 132 farmers commintted suicide, in 2003, 180 farmers committed suicide, in 2004, 524 farmers committed suicide and in 2005, 142 farmers committed suicide. In the bowl of Maharashtra where cotton is grown, the farmer feels that he is not even able to exist and perforce he has to commit suicide, then what to talk of desert lands of Rajasthan?

In the hillock lands like Uttaranchal, it will not be Vidarbha only, when it was through a PIL projected to Maharashtra Government that suicides are taking place, it was contested and ultimately, there was a special purview done by the High Court and ultimately, it came out of that purview that 294 farmers have committed suicide and the Government had to accept it. About Andhra Pradesh, less said the better. Same is the state of affairs of other surrounding States. Punjab which we call the greenest part or the granary of India, there also in every district, you will find farmers committing suicide. They are in debt trap and this trap is so binding that they cannot get out of it. I will quote again the figures, Mr. Vice-Chairman, sir, of how much debt an average farmer in Punjab has and it is Rs. 41576. Debt per farmer in Kerala is Rs. 33907, debt per farmer in Haryana is Rs. 26007 and in Andhra Pradesh it is Rs. 23965. It is virtually an endless whole story. In Rajasthan, my State, where 65 per cent of the area is desert, where 11 per cent population of the country lives, which is the largest and biggest State in the country as far as geographical area is concerned, but water share is only one per cent, there also debt is Rs. 18372. I cannot understand how the farmer can pay it. Either that is nullified or sooner or later he will commit suicide. There will be no other way out. Average debt performer in the country is 12,585 and this debt is not by the national banks or by the cooperative banks. A chunk of debt comes from money lenders who charge usurious rate of interest. Rate of interest maybe 25 per cent, 35 per cent, 55 per cent and in certain cases even 100 per cent. That kind of scenario is there. Munshi Pramchand had written about the main character, *Hori* in *Godaan*,, that the story of Indian farmer is the story of a person who lives a life of agony and for him death will be better than life. That state has not changed even after 58 years of independence. I have spoken about only one aspect of his plight. Apart from debt trap, the things that he needs, he is not able to get as Dr. Gill has pointed out. First thing is irrigation. We suffer from drought or we suffer from floods but right irrigation is usually not available to the farmers. Water which he needs for his crops is not available there. Seeds which he needs are not available there. Pesticides which he needs are not available there. Insecticides which he needs are not available there because they are all adulterated, they are spurious or they are at very high rate. He cannot afford to get that. So the basic inputs then we will say let there be urea, let there be DAP. He cannot afford to have them because they are very

costly and subsidy, which is given, does not go directly to him. It goes to those who produce them and it doesn't trickle down to him. That subsidy factor is as illusive for him as is the factor of crop insurance. Crop insurance also is a kind of facade or is a kind of imaginary, lucrative grant to him which doesn't give him real benefit because as was pointed out when it comes to the crux of how much loss has come, it will be calculated at the level of the Tehsil and he is a person who has suffered from hailstorm in a particular village and his crop output is zero. Even then, there will be no advantage. As it was today pointed out in the morning session if calamity is in the form of frost or calamity is in the form of sudden fall of temperature, it might cause 50 per cent loss of crop but there will be no compensation from the Government because according to all the rules or irrational rules, natural calamity does not include frost. Frost comes from heaven. Difference in teperature comes from heaven. It is not a man-made clalmity. It is god-made calamity and we don't call it natural clamity. what a travesty of truth it is for him. Apart from this, Sir, one more thing which bothers him is that When he is able to grow the crop then does he get the right price for it? This minimum support price, if you ask any farmer, he will never feel satisfied about it because those who fix up this price, they fix up in such a manner that he hardly gets any livelihood out of it. That is why it has been mentioned in the latest National Sample Survey Report that 40 per cent of the farmers, whose father, whose grandfather, whose great-grandfather were in agriculture business, who loved land as their own mother, are not willing to do farming business any more. खेती has become घाटे का धंधा. They are bonded labourers now. If you go to any farmer in a village and ask him whether he likes to do farming if he is able to get another alternative i.e., if he is able to get into an industry or if he is able to get a Government job, he immediately opts out. He is a captive labourer on his own farm, because he has no other alternative. That is the plight of not one person. But, it is the plight of — I would not call it 65 per cent population — 69 per cent population, which is dependent on agriculture. In terms of manpower, it comes to 75 crores. It is the destiny of 75 crores which we are discussing just now. The question is: Are 75-crore people, who are known as farmers, happy? They may be having a small plot. Sir, an average plot is not more than one hectare. They may be marginal farmers.

They may be labourers on farming. But, 75 crore people, one way or the other, depend for their livelihood on land. Do, they have some place under the sun? That is the question today. If this segment of population, which is the real Bharat, which is the real India, got some place under the sun, we would not have given them only 1.3 per cent of the Budget. Their contribution to our GDP would not have fallen from 45 per cent to 20 per cent or less than that and they would not have sold their daughters. They are selling them only becasue of the fact that they are not able to support them. This plight is man-made. This plight is made because of our inability to understand their real problems and not carring for them.

Sir, I would conclude only by saying that if farmer dies, India dies; if farmer lives, India lives. As Mahatma Gandhi had said, 'India lives in its villages.' And, the heart of the country would have thought about its six lakh villages. So, I appeal, through you, Mr. Vice-Chairman, Sir, to the House and request to put its best might in favour of that person who cannot speak, who cannot write and is illiterate. वह न बोलता है, न तोलता है and for him, Sahir Ludhiyanvi has said,

हर उस खोशा-ए-गंदुम को जला दो
जिससे न मयस्सर हो देहकां को रोटी

I will put it into English. He had said, "let every grain be burnt which does not provide enough sustenance to the man who produces it." अन्नदाता today is a beggar. अन्नदाता is dying. अन्नदाता is in hunger and something has to be done. I think, we can talk very long about his endless tale of woes. There are so many important points which have been beautifully raised by Mr. Narayanasamy. We are thankful to him for bringing such an important issue before the House. But you can see how many of us are interested out of the total strength of this House. This by itself is a telling commentary of how much we are interested in *kisan* and his plight.

Thank you very much, Sir, for bearing with me and giving me time to speak.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Thank you. Pilania for your good speech. Now, Dr. Prabha Thakur.

डा॰ प्रभा ठाकुर (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष जी, धन्यवाद। आपने मेरे निवेदन पर गौर किया और मुझे तीन मिनट का समय दिया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है, जो श्री नारायणसामी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस बात को सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और दो-तिहाई से अधिक किसानों के परिवार कृषि से प्राप्त आजीविका पर ही पलते हैं। कहने को किसानों को धरती का बेटा या अन्नदाता कहा गया है, लेकिन किसान आज जिन हालात से गुजर रहे हैं, उनसे भी पूरा देश परिचित है। यह सरकार भी इस बात को जानती है और इस बात से परिचित है, इसीलिए जो इस बार का राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, इसमें सरकार का संकल्प भी उभर कर आया है और कृषि क्षेत्र को, ग्रामीण क्षेत्र को और किसानों को इसमें प्राथमिकता दी गई है, लेकिन फिर भी इससे भी बढ़ कर कुछ करने की आवश्यकता है किसानों को गरीबी से, बदहाली से और निर्धनता से बचाने की आवश्यकता है और ऐसी स्थिति लाने की आवश्यकता है कि कोई भी किसान बदहाली, आर्थिक तंगी या ऋण की स्थिति में आत्महत्या न कर सके। इस संकल्प का जो प्रमुख विषय है या इसका जो उद्देश्य है, वह यह है कि किसानों के लिए ऋण नीति की उचित व्यवस्था की जाए, उनको दिए गए ऋणों में ब्याज को कम किया जाए, समय पर उनकी फसलों का उचित मूल्य दिया जाए। जो कृषि बीमा की प्रक्रिया है, उसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगी कि उसका और सरलीकरण किया जाए। इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगी कि किसान फसल तो पैदा कर देता है, लेकिन यदि उसे समय पर उसका उचित मूल्य नहीं मिला तो उसकी फसल होना या न होना बराबर है। पहली बात तो इस देश के अन्दर फसल का अच्छा होना और समय पर होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कही,पर अनावृष्टि है, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं पर बाढ़ है, कहीं सूखा है। इन परिस्थितियों से जूझते हुए आंधी, तूफान, गर्मी, सर्दी को झेलते हुए जो फसल पैदा हो और फिर यदि उसे उसका उचित मूल्य न मिले तो कई बार किसान के पास हताशा में आत्महत्या करने के अलावा कोई और चारा ही नहीं रहता, इसलिए यह जरूरी है कि सरकार इस पर विचार करे।

महोदय, इसके लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूं। वह यह कि जो नदी की जल एकीकरण योजना आरम्भ की है ताकि सिंचाई के साधन विकसित हों। कई जगह किसान की फसल इसलिए बर्बाद हो जाती है क्योंकि उसे खाली वर्षा के जल पर निर्भर रहना पड़ता है। जहां सिंचाई के संसाधन नहीं हैं, राजस्थान उन राज्यों की श्रेणी में आता है जहां सिर्फ सिंचाई के साधन की कमी से किसान मार खा रहा है और राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, मान्यवर, जहां एक बहुत बड़ा भाग रेतीला भाग है मरु-भूमि है। मैंने पहले भी कहा और आज भी कहना चाहती हूं कि वहां एक तो मरु-भूमि है और वह सूखाग्रस्त क्षेत्र है, जहां 4-4, 5-5 वर्ष हो जाते हैं और बारिश ही नहीं होती। तो मैं यह कहना चाहती हूं कि जिस प्रकार उत्तर पूर्वी क्षेत्र को दर्जा दिया है, जिस प्रकार पहाड़ी प्रदेशों को दर्जा दिया गया है, वहां के लोगों को, विशेष राज्य का, संरक्षण देने के लिए,

वहां के किसानों और गरीबों को संरक्षण देने के लिए, उसी प्रकार राजस्थान की सूखाग्रस्त स्थिति को देखते हुए और राजस्थान का जो अधिकांश भूभाग रेतीला है और उसकी मरु-भूमि को देखते हुए राजस्थान को भी एक विशेष राज्य की श्रेणी का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता है। पानी की जहां पर बहुत कमी है, इसलिए वहां के किसानों को राहत मिले, उन्हें विशेष सहायता केन्द्र से मिले। इस प्रकार राजस्थान का भी उत्तर पूर्वी राज्यों की भांति या जो पहाड़ी राज्य हैं, उसकी भांति राजस्थान के भी किसानों को, कृषकों को, गरीब जनता को उसका लाभ मिल सके। महोदय, मौसम भी कुछ वर्षों से बदल गया है। मौसम आगे-पीछे चला गया है। जो मौसम का समय होता था उसके हिसाब से न बारिश होती है, न सरदी पड़ रही है, न गरमी पड़ रही है। मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि मौसम विभाग को बारीकी से इसका अध्ययन करना चाहिए तथा किसानों के हित में पहले से ही यह बताया जाना चाहिए ताकि वे समय पर अपनी फसल बोएं, नहीं तो उनका बीज बिल्कुल बेकार हो जाता है और कई बार बीज इसलिए भी बेकार हो जाता है नकली खाद, घटिया बीज के कारण इसकी कैसे उचित व्यवस्था हो, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। किसान अपना समय बर्बाद करता है, मेहनत बर्बाद करता है, पैसा बर्बाद करता है जबकि घटिया बीज और घटिया खाद के कारण उसकी फसल बेकार हो जाती है। कृषि मंत्रालय में, विभाग में एक मौसम का तन्त्र भी हो। आज यहां सदन में बात भी हुई थी, जिसको विकसित करने की जरूरत है ताकि किसानों को पूर्व सूचना दी जा सके, ताकि वे खेती को बचाने के लिए उपाय कर सकें।

केन्द्र सरकार की और राज्य सरकारों की किसानों को सहयोग देने की, लाभ देने की जो भी योजनाएं हैं, उनके लिए जरूरी है कि उनका सही तरीके से प्रचार-प्रसार हो, चाहे वह दूरदर्शन के माध्यम से हो, चाहे अन्य संचार माध्यमों से हो, चाहे विज्ञापनों के माध्यम से हो, चाहे इसके लिए कैम्प लगाये जायें और किसानों को इसके बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है। अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, तो कैसी जमीन पर, कैसे मौसम में, उन्हें कौन सी खेती करनी चाहिए जिससे उन्हें लाभ मिल सकता है, जिससे उनकी खेती अच्छी हो सकती है, इसकी जानकारी दी जाए। इसके लिए राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार में एक अच्छे तालमेल की आवश्यकता है, इसकी मानिटरिंग करने के लिए एक अच्छा तंत्र विकसित करना जरूरी है और किसानों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। उनको जानकारी दी जानी चाहिए कि कौन सी लाभान्वित योजनाएं केन्द्र सरकार ने बनाई हैं, कैसे किसान उन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। किसानों को ऋण देने में तो बढ़ोत्तरी हुई है। केन्द्र सरकार ने किसानों को ऋण देने के प्रतिशत में बढ़ोत्तरी की है, जो प्रतिशत ऋण का बढ़ा है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन इसके साथ ही ऋण देने की जो प्रक्रिया है, वह सरल होनी चाहिए, किसान के ऋण की जो ब्याज-दर है, वह कम होनी चाहिए।

मान्यवर, इसके अलावा कहीं किसी जिले में या प्रदेश में सूखा पड़ता है, जो उस स्थिति में उस वर्ष का किसानों का ब्याज तो कम से कम माफ किया जाना चाहिए। ऐसा किसानों को बदहाली से बचाने के लिए, उनको आत्म-हत्या करने से बचाने के लिए बहुत जरूरी है, यही मैं निवेदन करना चाहूंगी।

मान्यवर, इसके साथ-साथ श्वेत क्रांति की तरफ भी ध्यान देना जरुरी है क्योंकि किसानों का दूसरा धन डेयरी है, पशु-पालन है, इसके जरिये से भी वे अपना पेट पाल सकते हैं। डेयरी उद्योग को कैसे बढ़ावा दिया जाये, डेयरी उद्योग का कैसे सशक्तिकरण किया जाये, इसमें किस तरह से किसानों को लाभान्वित किया जाये, इसके लिए भी कोई न कोई योजना विकसित की जानी चाहिए ताकि हरित क्रांति के साथ श्वेत क्रांति भी जुड़े और वह ज्यादा विककित हो। जिस प्रकार से महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुये हैं, उसी प्रकार से कृषि-आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की दृष्टि से कुछ ऐसा होना चाहिए कि किसानों के भी सेल्फ हैल्प ग्रुप बन सकें और जिनको को-आपरेटिव बैंकों के द्वारा ऋण दिया जाये और वे आपस में ही मिलकर कृषि-आधारित उद्योगों को लगायें और इस तरह से कृषि का पूरा लाभ लेने में सक्षम हों। वर्ना होता क्या है? किसानों को तो कुछ नहीं मिलता है, जो व्यापारी होते हैं, वे उनकी पैदावार की सामग्री कम दामों में ले जाते हैं, तेल निकालना हो जो उसे ले जाते हैं, उसका सोस बनाना हो, कुछ भी करना हो, तो कृषि का भरपूर लाभ व्यापारी ही उठाते हैं और किसानों को उसका लाभ नहीं मिलता है। ये ही मेरे कुछ सुझाव हैं। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं और स्वागत करती हूं। हमारी सरकार की नीति भी किसानों को लाभान्वित करने की है और मुझे आशा है कि केन्द्र सरकार इस दिशा में किसानों के लिए और कुछ कदम उठायेगी। धन्यवाद।

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI (Maharashtra): Thank you very much, Mr. Vice Chairman, Sir. I would like to start by thanking Mr. Narayanasamy for having provided an excellent occasion for a very comprehensive discussion on this subject.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): You are thanking me for the first time.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: I hope you will give me more occasions. We have discussed the question of agriculture, we have discussed the question of suicides, we have discussed the question of credit supply often, but the issue somehow gets fractured and little conclusion comes out of it because the framework provided for that debate is always fractured. I wanted to congratulate Mr. Narayanasamy, particularly, for the manner in which he has drafted the Resolution which

provides a comprehensive canvas for a regular debate on agriculture. And, luckily it comes during the Private Members' Business because if it were not in the Private Members Business, Mr. Narayanasamy might have become his usual garrulous, aggressive self and taken the attitude of 'my Party,' right or wrong, but on a Friday afternoon, we all become sane, quiet, and start thinking about the real problems involved.

Sir, in the first paragraph of his Resolution, he talks, correctly, of the miseries of the farmers. He talks of the misery of the farmers. In the second paragraph, he talks about the indebtedness of the farmers. In the third paragrapn, he talks of the natural causes, Sir, what is called in Hindi, the *Aasmani* causes for the farmers misery. And, in the fourth paragraph, he talks of the *Sultani* causes, that is, the causes coming from the Government action; the miseries caused by the Government. And, then, goes on to list all corrective measures that he thinks, are necessary.

I, particularly, appreciate Mr. Narayanasamy's Resolution because it starts by saying that even after more than five decades of independence, though overall the lot of farmers has not improved. The usual Narayanasamy I know that Narayanasamy that we know would have started by saying, since 1998, farmers' lot has gone down. I am happy that he has said that right since Independence, the farmers' situation has been declining. Because, that really permits us to understand what went wrong. Since Narayanasamy did use the word 'since Independence', I would like to recall the fact, that before Independence, when we were young *sainiks* in the Freedom Movement, the normal argument that we heard from the leaders was that all the problems of the farmers, of the peasantry were caused by the imperialists and the British. And, all that was required for the improvement of the lot of the farmers was that the British should quit in the first instance. Now, the British have gone,and, even a very conscientious person like Mr. Narayanasamy has to say that 50 years after Independence, the position has not changed. In fact, there was hardly a case known of a farmer having committed suicide during the entire British period, while it is happening in very large numbers right now under the Tricolour and under the Independence. Now, the question, naturally, arises, why? The British have left. The colonial, imperial exploitation, at least, formally has stopped. Have the farmers become lazy? Have the farmers become more addicted to drugs and

other alcoholic drinks, etc.? Has he become more illiterate? It doesn't appear so. The farmers are producing much more than they ever did. For example, before Independence, if they produced just three quintals of wheat per acre, they are now producing as much as 20-24 quintals. I could quote similar examples even about cotton, etc., where productivity has gone up by more than eight or ten times. Sir, there is not a single industry where the productivity since Independence has gone up by even 300 per cent. Now, the persons who have not increased their productivity by even 300 per cent, are becoming the prime movers of the Indian Economy, and they offer to help farmers, they offer to give subsidies to the farmers; this is something which is difficult to understand. After the Imperialists, in the pre-freedom speeches the other guiity people were the moneylenders and the landlords. Soon after the Independence, at least, the moneylenders became, formally banned; landlordism continues even now, but as the Minster for Agriculture said the other day, after the ceiling laws, the tenancy legislations, and the population is increase, now, there is hardly any accumulation of land holdings worth the notice. So, the moneylender has gone; *the zamindar* has gone, the British Imperialists have gone, the farmers have increased their productivity; all the same, if I were to put what Narayanasamy has put in the first sentence—in just two figures, if you permit me - it is like this:, "in 1951, the population dependent on agriculture was as much as 70-75 per cent." It has come down now. It is around 66 per cent now, according to the latest figures. But, at the same time, earlier agriculture contributed about

4.00 P.M.

71 per cent.of the gross Domestic Productivity, now, it is contributing only 27 per cent Part of it is due to the fact that- the service sector has become more important - But the agricultural productivity and gross output have increased, all the same, the proportion of people dependent on agriculture has remained, practically, constant, the contribution to the national basket has declined very substantially. Now, before I make further comments, I would like to give a certain picture about what the role of agriculture in any developing economy is. Farmer is the only producer who multiplies product or, who multiplies the input. For example, it is only the farmer who puts in one seed, and thanks to the utilisation of the cosmic energies, including the Sun and the Rain, a thousand-fold multiplication takes place. From one seed, thousands of grains grow up. This kind of a miracle does not happen in any other industry. Even in the case of the most efficient of industries, I have not seen, one kilo of

iron being put from one end and two kilos of iron coming out from the other end! That does not happen anywhere. But, the remarkable thing is, those who do not bring about any multiplication of product, or multiplication of incomes, are better off. They are the people who say, we will subsidize the farmers; we will have to help them.'

There is something very curious about this. I think, the important question that is to be asked as regards the first paragraph of Mr. Narayanasamy is—why did this happen? The British went, the moneylenders went, the *Zamindars* went; then why did this happen? Even though the farmers continued to inrease their productivity, the system remained such. I would like to make it clear here that it is not necessarily the political system. I am not blaming only the Government or any Party. The entire Indian economy, as also the entire society in most of the countries of the world, develop such social institutions that the farmers would always remain needy. As soon as the harvest season comes, he would be pushed to the market.

Sir, I shall give you a good example of this, In the whole of India, most people follow the Hindu religion. But even amongst the Hindus, you will find that their most important festivals don't come together. If they have the same religion, their festivals should be failling together, But, we have the earliest festival coming in Bengal, that is, the *Durga Puja*. Some two or three months later, you would have *Diwali* in Western India, and in the South, Pongal fall at the end, towards the mid *Rabi* season.

Now, you will understand, Sir, that in Bengal, they grow varieties of rice which blossom very fast; the crop would be ready in three or four months. In Maharashtra, the Jowar that they grow generally takes five to six months to be ready for harvest. And for Pongal, in Tamil Nadu, they use varieties of rice that take seven to eight months to ripen.

The most important festivities of the Hindus are celebrated not when the crop is ready, not when the cutting is done, not when the bundles are tied up, but just when the crops are standing in the fields, ready to be harvested. If at this time the festival occurs, naturally, the farmer, even if he does not care for the festivities himself, has to think of this children and his family. And, therefor, he rushed towards the market and he has to make a sale even before he is really ready to sell. As Sharuyu Daftary

mentioned once, 'the whole social infrastructure depends on keeping the farmer needy'. That is very important, he says. Keep the farmer needy; otherwise, the whole society would collapse.

Now, Sir, I shall try to explain the Development Theory in just a few minutes. A farmer grows a hundred grains, and then, if there are three or four brothers who are cultivating together, after some time they would start asking themselves the question - what is the point in producing more and more grains? If you go on planting the seed and multiplying it every year, we would produce food, which we would not need, which we would not be able to consume ultimately.

Under these circumstances, what would they do? What they would do is, the four brothers would sit together and they would discuss it among themselves. They would say - 'look here, there is no point in increasing the foodgrains production now. We better withdraw one of us brothers from agriculture, and send him to the forests, so that he could cut trees, bring timber and we shall construct, at least, a wooden house where we could shelter ourselves in winter and during summer'. The second year, there would be the same problem again and then they would say - let us send somebody who would be prepared to get some fibres for us, some clothing for us.

In this way, diversification would continue until their family would be producing not only food but also electrical instruments such as fans, and even aeroplanes and tanks. That is the natural process of economic development.

The agriculture lays the golden eggs, and if they are properly used this can result into the overall prosperity of the society as a whole. However because of the greed people want to slaughter the chick, the hen that lays golden eggs and, therefore, the entire history of mankind is the history of taking away 999 extra grains that farmer produces. The old kings did the same thing. When foreign invaders came, they all wanted to take away the multiplication and the surplus in the agriculture. When the British Imperialists came, they also came for taking away or robbing the argricultural surplus in India. That is the history. The entire human history is the history of evolution of methods for exploiting the farmer. I will try to explain this by the example of Japan. Sir, we all admire Japan's

progress. Everybody knows that Japan has tittle land and very small landholdings and still it is one of the most industrially advanced countries in the world. How did it happen? There were documents to show that the Japanese Prime Minister as early as in 1921 started offering for the Japanese paddy growers a support price which was three times the international markert price, and today it is eight times the international market price. When the farmers got extra money, they started building little cottage industries. At least, when I was in the school, Sir, we read about, not the huge giant industries of Japan, but we read about the cottage industries in Japan where handicrafts and little things were produced. These small-scale and cottage industries blossomed into the giants of today. That is what happens if the Government is such that it is not tempted by the gold in the eggs and doesn't try to cut the hen. In India, that is precisely what happened. The Indian agriculture is a losing proposition. The previous speaker, Dr. Pilania, also mentioned about this. It is something which does not need the statistics. It is everday experience if you really have eyes to see. The farmers' sons who go to the college, who even have graduation in Agriculture, never come back to help parents in agriculture. Why is it so? It is because the farmers' sons know that agriculture is not a profitable proposition and there is no point in coming back to agriculture. Similarly, or, how often have you seen a city girl marrying a farmer's sons? A city girl might marry the son of a Director of a sugar factory or the son of a Minister who happens to have land. But city girls have stopped marrying children of farmers because they know that if she is married into a farmer's family her life will be entirely miserable and, therefore, she turns her back. We have all this experience but we never register it. In 1980, for the first time, Sir, I made a calculation that the loss that is caused to farmers because of the adverse governmental price policies was of the order of Rs. 10,000 crores. Later on, Ashok Gulati, who has now become internationally famous for his work on negative subsidies wrote his thesis and said that the loss caused to the farmers because of the anti-farmers governmental policies was of the order of Rs. 10,000 crore. It is the same figure. The official economist lobby, at the same time, was saying that farmers are heavily subsidised. In fact, Ashok Mitra, the famous Communist-Economist, in his book 'Terms of Trade and Class Relations' actually states that Indian farmers are so heavily subsidised that they are the better-off people in this country and that is why they have got the

reins of political power. Can you imagine a more absurd statement from a person who claims to be an economist? But the Communists have always been wrong about their agricultural doctrines, whether it is Marx, Lenin or Stalin.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Nobody is here, then why are you saying this?

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: They will, probably, read about it. Then, the question is: how can this happen? For example, till 1965, that is, the epoch of Pandit Nehru, as Mr. Narayansamy has mentioned, if the farmer had good crops, the prices fell and nobody came to support them. And, if we had bad crops and there was a famine, then the farmers would be forced to give levy of foodgrains and the levy prices were often much less than the market prices. Very often, it happened that the farmers had to purchase the *jawar* in Maharashtra at elevated prices and give them at lower prices as levy. That was the kind of exploitation that was taking place. In case of sugar, when I got into the farmers' agitation, 70 per cent of the sugar was taken away as levy at a price which was just 50 per cent of the market price. There was a period when my friend, who used to be a Member of this House, Shri Bhupendra Singh Mann, was punished by the Court because he was carrying just five kilos of wheat from Punjab to Haryana and crossing the State borders with wheat commodities was a punishable offence. In Maharashtra, till recently, cotton could not be given to Andhra Pradesh and Madhya Pradesh even though the prices there were Rs. 200 to Rs. 300 per quintal higher than the prices offered by cotton monopoly. When the farmers could get better prices for onion, there would be an immediate ban on the export of onion with the result that the price of onion came down. This was a systematic manner in which the Government of India right till 1965 and even much later, deliberately depressed agricultural prices. I am using the word 'deliberately', and I am going to support it. You will find that deliberation in Shri V.T. Krishnamachari's introduction to the Second Five Year Plan, where he said in effect that if you want to have socialist industries, then you would have to take away the surplus from agriculture in order to develop primary capital for the socialist industry. Now, this was exactly what was said in the Soviet Union in the days of Stalin, by Praebrozensky and Bukharin. Stalin sent tanks on Russian farmers calling them kulaks. We did not use any uncouth methods like that. We

used rather sophisticated and civil methods but the effect was equally disastrous. In brief, what happened was that after 1947, the British went away, but the British policies continued. I can say that if the white British left, their place was taken by brown British and the policies continued to be the same. The beneficiaries were no more Lancashire and Machester, they were probably Kolkata and Mumbai, but the policies remained the same. Since 1980, we have had a running debate with the official economists who claim that the farmers have very high subsidies, and those like me who claimed that the farmers have negative subsidy. And, I had to explain to them what the negative subsidy is, and the way I explained it was very simple. I think, I should say it even here. Sir, after I became a farmer, one of the first crops I took was cucumber because in Pune, cucumber was a famous variety.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Please, wind up.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: When I started sending them to Bombay — at that time it was Bombay and not Mumbai — I got communication saying that they had sold my cucumber and I would get about Rs. 300. The second time, I got Rs. 128. The third time, I got a letter saying that they had sold it to the best of their capacity of cucumbers but the proceeds could not cover even the transport and the portage and, therefore, I should send them Rs. 138. so, they sold my cucumber; they kept the money and wanted me to give them additional Rs. 138. Now, this is what I call negative subsidy - when the price realised by the farmer is less than the cost of production of the farmer or when the price that the farmer receives is less than the price that he would have realised in a hypothetically free market, then it is called negative sussidy. What I said was finally vindicated in 1986 to 1989 when on the occasion of the WTO negotiations, Mr. Pranab Mukherjee, the then Commerce Minister, made a statement. He made a statement that it is a fact that in India a negative subsidy was imposed on farmers. This is a confession. This is not a party matter. And, at the same time, Japan made a declaration to the WTO that our price policies are such that if the cost of production is 100 rupees then the farmers should get 190 rupees. The European Union made a statement that our policies are such that if the cost of production is 100 rupees, then the farmers should get 165 rupees, and, the United States stated that our policies are such that if the cost of production is $ 100, the farmer should get $ 135. The Government of India under the

signature of Shri Pranab Mukherjee — I had discussed this matter with him even at that time — gave a categorical statement that our policies are such that even if the cost of production is 183 rupees, the farmer will not get more than 100 rupee! There were some disputes, statistical dispute and theoretical dispute as to whether that was 118 or 183 but there was no dispute about the fact that the farmers have always worked under the negative subsidy.

Even on the eve of leaving for Hong Kong, the present Minister for Commerce, Shri Kamal Nath admitted that even today, the Indian farmers are working under a system of negative subsidy. If it is this negative subsidy that makes agriculture a losing proposition, then, naturally the solution in Part 4 of the resolution have to 'change'. For example, examining the remedies proposed by Narayanasamy, we come to. He talks of the waiver of loans, he talks of fresh loans being made available, he talks of procurement policies being improved, and, he also talks of a system of insurance and of a better system of market intervention. All these things give an impression as if the farmers can survive only if there is a godfather in the Government. This kind of an approach, in case of a farmer who actually carries out a physical multiplication of income shows that there is something which is hidden.

What I would say is — Dr. Gill also raised that point — that it is a fact that in the present epoch, we would have difficulty in competing with countries like America and Europe because they have larger farms, they are highly subsidised and mechanised, they have technology. A Kisan leader in Uttar Pradesh said, United States and Europe are like wrestlers who have been fed on *badam* and other nutritious things while our farmers have been starved for fifty years. How do you expect our starved farmers to have competition with the world-class wrestlers? I would like to say that that wrestler has some weak points. Dr. Gill also mentioned that we have a great endowment of solar energy, abundant sun shine, and, we have adequate water resources; and that is going to clinch, that is going to be a factor to finally decide as to who will win in the international competition. What is required is that we ought to make up. It is not that we are asking for favours from the Government. As the Chairman of the Task Force on agriculture to advise the previous Prime Ministers on the WTO situation, Sir, I know, and, it is a factually established statistical data, that in the year 1996-97 according to the Government's statistics

— in one year alone, the loss caused to the farmers because of the negative policies of the Government was Rs. 1,13,000 crores. All this is in Government's document and, we calculated that since 1980 till 2001, the loss caused to the farmers because of the anti-farmer governmental policies was as mush as 300 thousand crores of rupees. That is the sum that the Government owes the farmers.

Don't talk of how much money the farmers owe to the banks, how much money they have to pay for the electricity. The important thing is that the Govt. has taken away 300 thousand crores of rupees from them. That is, probably, as Lord Keynes said, "In Economics bygones are bygones". We cannot go back on but, what is important is that when the Government spend at least Rs. 300,000 on providing the infrastructure, that would make the farmer competitive in the global market. For example, we need to have some of the important things. The first thing, I would like to say — I hope Mr. Narayanasamy is listening — is that the agriculture shuold be privatised. Today, agriculture is highly dominated by the State. The land belongs to the Government, you know the principle of *eminence juris*, therefore, the farmer is only a sort of a holder or a tenant of the land and the land can be taken away from the farmer at the pleasure of the Government. This is a thing which discourages farmers from carrying out any investment in the land.

Secondly, the inputs are all controlled by the Government and, therefore, the prices often are higher than the prices in the competing countries. What we will have to do is to open up so that the Indian farmers get their inputs at about the same price as the farmers elsewhere. Thirdly, Sir, there should be an opening up of the output markets as well. India is not one market. India is a fractured market and before we go into a globalised system, where the division of labour is carried out according to the comparative advantage, we ought to have a specialisation between various regions in India, depending upon the comparative advantage. For example, there is absolutely no reason why Bengal should specialise in jute. There are other States which can produce much better jute at a much lower cost. But that kind of a division of labour, that kind of an apportionment and allocation of resources can take place only in a market economy; in a Government-controlled economy, that kind of a rationalisation is impossible. Then, we need to have is we should have a sophisticated market, and I congratulate the present Government--

Narayanasamy*ji*, if you are listening -- I am glad that the system of Agriculture Produce Marketing Committees is being withdrawn and we are encouraging the system of organised retail trade. And, I must congratulate the present Finance Minister because he has allowed even the Foregin Direct Investment in retail trade. Further, need to have an informatics infrastructure and a network as well where the farmers who have to go into the global market will be able to see on the internet what kind of prices are prevailing in different markets, what are the arrivals and what are the departures in different countries.

Then, Sir, we ought to have a large network of scientific laboratories. If you want to go into global market, you must know what is the quality of your products. How can you know that, unless you have a laboratory nearby?

Unfortunately, when the Food Safety and Standards Bill was being discussed, we found that in the country, as a whole, there were only 17 laboratories which could take care of the whole range of product. What we need to have is, every science college at a *tehsil* place upgraded into a scientific laboratory that can become a food-testing laboratory. That is what will do good to the farmers.

Sir, the last solution which I would offer to Mr. Narayanasamy is an important solution and that is the point that Mr. Pilania mentioned. The land is treated as mother therefore, sacred, etc. It is just a lot of nonsensical poetry. My experience shows that every farmer and every farmer's son, who gets a chance to find a job to get into the industry or a trade, leave agriculture because he knows where his survival is. Therefore, we ought to provide a land market, a developed land market, and, I am glad that the Deputy Chairman of the Planning Commission, Dr. Montek Singh Ahluwalia, has accepted this suggestion. We ought to permit the farmers, who find themselves psychologically or physically incapable of meeting the challenges of the global market, to leave. And, if there are others, who have better managerial abilities and who have more investible funds, should come in. We have been following a policy where even Amitabh Bachchan cannot become a farmer unless he produces a certain certificate. Sir, I had difficulty in becoming a farmer after returning from the United Nations. I was allowed to become a farmer only when in one year my annual income came to less than Rs. 10,000.

If you are poor enough, you can become a farmer. But if you have money, then you cannot become a farmer. That is the kind of wrong exit and entry policy for the agriculture which will have to be removed.

The Green Revolution succeeded. And the Green Revolution meant employment of the hybrid seeds, employment of chemical fertilizers and chemical pesticides, and new technology. Now, this was not within the intellectual or mental scope of many people, but they were able to leave the agriculture at that time because of a large number of anti-*jamindari* Acts and Land Ceiling Acts. That is how Late P.V. Narasimha Rao's forefathers were able to leave their 3000 acres of land in Andhra Pradesh and come out and later on prosper in Delhi. The reluctant farmer will have given some kind of a golden handshake and some kind of a voluntary retirement scheme for the farmers who find life impossible. Today, farmers are committing suicides because there is no exit, they are sort of trapped, and they will have to be provided some vent if you want to bring down the number of suicides. Before concluding, I once again congratulate Shri V. Narayansamy for having provided a very broad canvass permitting a comprehensive discussion of various issues and more importantly not just description of how miserable the farmer is but also discussion of why has it happened despite the British exit, despite the moneylender going away, and despite the *jamindars* going away, the farmer continues to be in a situation much worse than he ever was under the British regime. Thank you very much, Sir.

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री नारायणसामी जी द्वारा एक महत्वपूर्ण संकल्प पर चर्चा प्रारंभ की गई है। यह संकल्प हमारे देश की दो-तिहाई जनता से सम्बन्धित है। ज्यादातर लोगों की जीविका का साधन खेती ही है। आजादी के बाद खेती के लिए जितना हमें विकास करना चाहिए था, वह नहीं कर पाए। खेती के लिए पानी, बिजली, कृषि के अच्छे यंत्र, खाद, बीज आदि की आवश्यकता होती है। जब हम दूसरे देशों से अपनी कृषि की तुलना करते हैं, तो हम उसमें बहुत पीछे हैं, जबकि हिन्दुस्तान का किसान उन दूसरे देशों के किसानों से ज्यादा मजबूती से काम करने में समर्थ है, ज्यादा शक्तिशाली भी है और काम करने में रुचि भी रखता है, लेकिन हम उन्हें साधन उपलब्ध नहीं करा पाए हैं।

आज जब हम सिंचाई की बात करते हैं तो हमने इसके लिए कुछ बड़े-बड़े तालाब बनाए हैं, बांध भी बनाए हैं। बांध बनने से एक एरिया के अन्दर ही पानी गया है, लेकिन नदियों पर बांध बनने के बाद जहां से होकर वे नदी-नाले जाते थे, दूसरे एरियाज में जाने पर पानी की कमी आ

गई। इसलिए सरकार ने इसका सोल्यूशन निकालने के लिए नदियों को जोड़ने का एक संकल्प किया था। यदि सरकार उस संकल्प को पूरा करती है, तो मैं यह मुनासिब समझूंगा कि हम किसानों के लिए सिंचाई के पानी की समुचित व्यवस्था करने में सफल हो पाएंगे। कृषि के लिए सिंचाई एक महत्वपूर्ण चीज है। पहले कुओं से, छोटे-छोटे तालाबों से सिंचाई होती थी, लेकिन आज जब हमने बड़े-बड़े बांध बना लिए हैं, तब भी हमें उन बांधों से कृषि की जमीन तक पानी पहुंचाने में कई तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कहीं नहरें नहीं हैं और नहरें बन गई हैं, तो इतना पानी उपलब्ध नहीं है। अब जैसे राजस्थान में कई ऐसे बंध बने हैं, जैसे पाचना बंध करौली में बना, उसका फायदा कुछ गांवों को मिल रहा है, लेकिन जिस नदी पर यह बंध बनाया गया है, पहले वह जिन गांवों से जाती थी, उसका पानी कभी खत्म नहीं होता था, बिजली की मोटर चलती और पानी आ जाता था। आज स्थिति यह है कि घंटे भर भी मोटर नहीं चलती है। इसलिए आवश्यक हो गया है, माननीय मंत्री जी, कि आप चाहे कुछ भी करें, लेकिन पानी की व्यवस्था के लिए सरकार नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम जो हाथ में लेना चाहती है, उसमें जल्दी कार्रवाई करें और केन्द्र सरकार के पास जो कृषि के लिए पानी की योजनाएं आई हुई हैं, उन योजनाओं को आपका मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय आपस में बैठकर जल्द मंजूर करे, उनको चालू करे, जिससे किसानों को जल्दी से जल्दी फायदा मिल सके।

महोदय, मैं जिस प्रदेश से आता हूं, उस प्रदेश की हालत बहुत ही दयनीय है। वहां वर्षा होती नहीं है, हर साल अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। आज भी स्थिति वहीं है। पिछले 20-25 सालों से राजस्थान के अंदर किसी न किसी हिस्से में अकाल की स्थिति बनी रहती है और कई बार तो ऐसी स्थिति हुई है कि पूरे राजस्थान में ही भयंकर अकाल हुआ है। सिंचाई के लिए हम पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि उस पैसे का प्रयोग कैसे होता है? यहां बजट में भी इसके लिए पैसा रखा जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के बजट में भी होता है, लेकिन उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि देश के अंदर जो प्रदेश सूखे से प्रभावित रहे हैं, वहां पानी की व्यवस्था का काम हो। हम यहां आज इस बात को कह सकते हैं कि राजस्थान की भूमि इतनी उपजाऊ है कि यदि समुचित रूप से उसे पानी मिल जाए, तो हम दूसरे देशों से जो गेहूं इम्पोर्ट करने की बात कर रहे हैं, इतना गेहूं राजस्थान की भूमि से आपको मिल जाएगा और आपको इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

महोदय, दूसरा कृषि के लिए बिजली जरूरी है। आज बिजली की स्थिति यह है कि किसान को बिजली के कनेक्शन तो दे दिए जाते हैं, मगर उसे सर्दी की रात में भी बिजली नहीं मिलती। भयंकर सर्दी में तो किसान को एक दो घंटे बिजली मिले, दिन में तो मिलना मुश्किल ही है, लेकिन रात को तो एक दो घंटे बिजली मिले, आठ घंटे न मिले, बारह घंटे न मिले। आप देख लो किसान की क्या स्थिति है? हम तो किसान के घर से आते हैं, देखते हैं कि किसान किन

कठिनाइयों में अपनी खेती की सिंचाई करता है, बिजली की क्या-क्या कठिनाइयां भुगतता है। हर राज्य में बिजली के लिए किसान से मिनिमम चार्ज तो ले लिया जाता है, लेकिन उसे बिजली दी नहीं जाती है और उससे पैसा लेने में राज्य कोई रहम भी नहीं करता है। इसलिए आप देश के अंदर नीति बनाइये कि किसान से यदि बिजली का मिनिमम चार्ज लिया जाए, तो उतनी बिजली उसे मिलनी चाहिए अन्यथा बिजली के पैसे को कम किया जाए। दूसरी ओर देश के अंदर किसान सारी कठिनाइयां भुगतता है, उसके बाद भी वह फल-फूल रहा है। चाहे सरकार का प्रभाव पड़े, चाहे पैसे वाले जो साहूकार हैं, जिनसे ऋण लिया जाता है। उनका प्रभाव पड़े, चाहे बिचोलियों का प्रभाव पड़े, वह सारी कठिनाइयां तो किसान भुगतता ही है। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदाएं भी किसान को भुगतना पड़ती हैं। आज सुबह ही प्राकृतिक आपदा के बारे में एक चर्चा हो रही थी कि किसान को सर्दी और पाले से यदि खेती में नुकसान हुआ है, तो उसकी क्षति-पूर्ति के लिए नाम मात्र की सहायता दी जाती है। कृषि मंत्री जी, आपको अपनी नीतियों में प्राकृतिक आपदा, चाहे बाढ़ से नुकसान हो या सूखे से हो, चाहे सर्दी और पाला पड़ने से हो, ओला पड़ने से हो, किसान को सहायता देने के लिए, राहत देने के लिए एकरूपता इसमें बनानी पड़ेगी। आप और कुछ नहीं कर सकते तो आप बीमा योजना लागू कर दें खेती के अंदर, जिसमें बिना किसी शुल्क के उनकी खेती का और उनके पशुओं का बीमा होना चाहिए। आज कृषि-यंत्रों के लिए, पम्प सैट के लिए किसान बैंकों से ऋण लेता है, पानी का इंजन दस या पन्द्रह हजार का आता है। आज खेती में यदि लागत को देखें और उसकी तुलना पैदावार से करें, तो हम पाते हैं कि किसान की लागत भी पूरी नहीं होती। उसने पन्द्रह हजार का जो पम्प सैट लिया है या बिजली की मोटर ली है, वह किसान उसका कर्ज भी नहीं चुका पाता है और यदि किसान कर्ज भी नहीं चुका पाता है, तो फिर इस देश के अंदर कौन सी नीति है। गरीब किसान की जमीन को तो नीलाम कर दिया जाता है, लेकिन पूंजीपतियों के दो-दो, तीन-तीन हजार करोड़ रुपए राइट-ऑफ कर दिए जाते हैं, यह कौन सी नीति है? इस देश के किसान को यदि जिंदा करना है, उनको यदि मजबूत करना है, तो इस नीति को बदलना पड़ेगा।

आखिर में मैं, कृषि मंत्री जी, एक बात और कहना चाहूंगा कि समर्थन मूल्य फसल का आप देते हैं और हर साल घोषित भी करते हैं, लेकिन आपके समर्थन मूल्य की नीति जब तक लागू होती है, तब तो किसान अपने जिन्स या अपनी पैदावार को बेच चुका होता है। उसका फायदा कौन उठाता है? बड़े-बड़े सेठ, पूंजीपति, जो मंडियों में बैठकर उसे खरीदते हैं, वे ही उसका फायदा उठाते हैं। मैं आपको अब की बार की बात बताता हूं कि आपने सरसों का समर्थन मूल्य दिया है 1700 रुपए, लेकिन किसान की सरसों तो बिक चुकी है और आप उसे 1 मार्च से खरीदना शुरू करेंगे, तो किससे खरीदेंगे। आप इन बिचौलियों को रोकिए। किसान को समय पर उसकी पैदावार का मूल्य मिल जाए, आप ऐसी व्यवस्था करिए, खाली समर्थन मूल्य घोषित करने

से काम नहीं चलने वाला, बल्कि किसान को उसका लाभ मिलना चाहिए। शुरू-शुरू में सरकार उसको खरीदती है, लेकिन खरीदने के लिए स्टोर कम खोले जाते हैं। सारे स्टोर एक साथ क्यों नहीं खोल दिए जाते? इसलिए मेरा कहना है कि कहीं न कहीं कमियां हैं। कृषि मंत्री जी, मेरा कहना है कि आप किसानों को आधुनिक खेती की ट्रेनिंग दिलाने की व्यवस्था करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सदस्यों के सुझाव सुनने के बाद बोलने की इजाजत दी है।

उपसभाध्यक्ष जी, हमारे सम्मानित सदन के माननीय सदस्य श्री वी॰ नारायणसामी जी यहां एक संकल्प लाए हैं, जिस पर सदन के अनेक सदस्यों ने अपने अमूल्य सुझाव और कृषकों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की है। माननीय श्री फागुनी राम, माननीय श्री जयन्ती लाल बरोट, माननीय श्री एम॰एस॰ गिल, माननीय डा॰ ज्ञान प्रकाश पिलानिया, माननीया डा॰ प्रभा ठाकुर जी, माननीय श्री शरद अनंत राव जोशी जी और माननीय श्री मूल चन्द मीणा जी ने अपने सुझाव और किसानों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है। मैं इन सभी सदस्यों के प्रति आभारी हूं और कहना चाहता हूं कि आपने जो अपने अमूल्य सुझाव यहां प्रकट किए हैं, किसानों के प्रति आपने जो चिंता जाहिर की है, सरकार निश्चय ही आपके सुझावों के अनुरुप देखेगी कि किस तरह से हम किसानों की मदद कर सकते हैं और किस तरह से किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलने की हम एक अच्छी पहल कर सकते हैं। हमारी यू॰पी॰ए॰ सरकार के प्रधानमंत्री जी एक अर्थशास्त्री हैं,.... उनकी अपनी एक सूझ-बूझ है और जब किसान की दशा ठीक होगी, देश के अन्दर कृषि की अर्थ व्यवस्था ठीक होगी, तब देश भी मजबूत होगा। हमारी सरकार ने इस चीज़ को पूरी ईमानदारी के साथ लागू करने की कोशिश की है।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता जाहिर की है, निश्चित ही हम इन बातों को गंभीरता से ले रहे हैं। यूपीए सरकार से पहले एनडीए सरकार थी और उस समय आत्महत्या का दौर बड़े पैमाने पर चला था ...(व्यवधान)

श्री दत्ता मेघे (महाराष्ट्र): वह आज भी वैसा ही है।

श्री कांतिलाल भूरिया: इस चीज़ से पूरा देश चिन्ताग्रस्त था। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और यूपीए की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यह विचार किया कि चूंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं, इसलिए किस तरह से सरकार की तरफ से उनकी भरपूर मदद की जा सके। बैंकों के माध्यम से जो फाइनांस दिया जाता था, पहले वह 80,000 करोड़ रुपये थे जिसे बढ़ाकर अब

1,05,000 करोड़ कर दिया गया है। हमारा ऐसा अनुमान है कि आने वाले डेढ़-दो वर्ष के अन्दर हम उसे 1,15,242 करोड़ कर देंगे। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपीए सरकार ने इसे पूरी ईमानदारी के साथ लागू करने की कोशिश की है। इसके साथ ही साथ किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए, कृषि बजट के मामले में आपने पहले यह देखा होगा कि कृषि के लिए बजट में 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान था, अब उसे बढ़ा कर 6020 करोड़ रुपया कर दिया गया है।

हमारे देश में बहुत बड़े-बड़े वैज्ञानिक हैं और उन वैज्ञानिकों के माध्यम से अच्छी किस्म व अच्छी नस्ल की फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, किसानों के घरों में खुशहाली लाने के लिए हमने अच्छी नस्ल के बीजों की व्यवस्था की है। इसके लिए कृषि अनुसंधान परिषद् (ICAR) में अनुसंधान के लिए हमारी यूपीए सरकार ने 1150 करोड़ रुपये अलग से उपलब्ध करवाएं हैं और हमारे वैज्ञानिक उसमें पूरी ईमानदारी के साथ काम भी कर रहे हैं।

इस प्रकार जो स्थिति पहले बनी थी और जिस प्रकार से पहले किसानों के अन्दर आत्महत्या की जबरदस्त प्रवृत्ति बन गई थी, उसे कम करके हमने किसानों को सही राह पर लाने की पहल की है। इससे काफी फर्क भी पड़ा है। निश्चित ही किसानों को उभारने के लिए और उनकी दशा को सुधारने के लिए यूपीए सरकार वचनबद्ध है और यूपीए सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम बनाए गए हैं, उनके तहत जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उन व्यवस्थाओं को हमने पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया है और आगे भी हम लोग उसे करने की पूरी कोशिश करते रहेंगे।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 21 प्रतिशत एवं कुल निर्यात में लगभग 11 प्रतिशत का योगदान है। इसके माध्यम से देश के 55 प्रतिशत से अधिक लोगों को रोज़गार प्राप्त होता है और लगभग 650 मिलियन लोगों को आजीविका के अन्दर सुरक्षा प्राप्त हुई है। पिछले कई वर्षों से भारत कृषि उत्पादों का निबल निर्यातक रहा है। कृषि की उल्लेखनीय प्रगति ने देश को खाद्य एवं अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया है। ये सभी आंकड़े देश के समग्र आर्थिक और सामाजिक कल्याण में कृषि की उपलब्धियों को रेखांकित करते हैं।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, इस प्रकार आपने देखा कि हम लोग काफी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई है कि हमारे सामने कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। मौसम में कई प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं साथ ही साथ कभी सूखा पड़ जाता है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, इस प्रकार की आपदाओं के कारण हमारा जो लक्ष्य बनता है, जिसके मुताबिक हम पूरे वर्ष का कार्यक्रम बनाते हैं, हम अपने टार्गेट को पूरा नहीं कर पाते हैं। इन सब चीज़ों के कारण किसानों को कई प्रकार की तक़लीफों का सामना करना पड़ रहा है।

कई बार उन्हें समय से ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है, कई लोग अपनी शराब इत्यादि बुरी आदतों से घिरे हुए हैं, कई किसान सेठ -साहूकारों के ऋण के कारण दबे हुए हैं, हमने इन सारी परिस्थितयों को देखा और इन परिस्थितियों से निपटने के लिए यूपीए सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि किसानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध हो। जो किसान डीफॉल्टर हो गए हैं, जिनके लिए बैंको ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, यूपीए सरकार ने उनके लिए वन टाइग सैटलमेंट का एक फॉर्मूला निकाला है। उस फार्मूले के तहत, जितने किसान ऋण से दबे हुए हैं उनको किस तरह से हमको उबारना है, तो आपस में मिल-बैठ करके, उसका सैटलमेंट करके, आपसी समझौता करके, उनके ब्याज और मूलधन को बराबर करके, उसको कम करें ताकि उनको फिर से बैंक से ऋण मिलना शुरू हो जाए तथा उनके लिए जो बैंक के दरवाजे बंद थे, वे खुल जाएं। इस तरह 50 लाख किसानों में हम जोड़ रहे है। यह चिंता यू॰पी॰ए॰ सरकार ने की है और उस बात को लेकर किसानों को जहां-जहां तकलीफे आ रही थीं उन तकलीफों को दूर करने का यह हमारा प्रयास हुआ है। तो निश्चित ही उसमें जरूर काम होगा। साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मुख्यतया यहां उस बात को लेकर खाद्यान्न के संबंध में 1993-94 के दौरान केवल 184.26 मिलियन मैट्रिक टन का उत्पादन हुआ करता था। अब 2005-2006 के दौरान बढ़कर 200 मिलियन टन से भी अधिक हो गया है। इस प्रकार गैर खाद्यान्न फसलों और बागवानी फसलों की भी वृद्धि हुई है। सिंचाई से बीजो में वृद्धि करने का प्रयास सुगम बना दिया है।

उसी तरह से किसानों की एक जो तकलीफ थी, उसके लिए भी भारत सरकार ने कई कठोर कानून बनाए हैं। विभिन्न राज्यों में इस कानून का पालन होता है। किसानों के सामने नकली बीज, नकली खाद और नकली दवाइयों की समस्या सामने आती हैं। इसके जो सप्लायर हैं, जो कम्पनियां हैं, उनसे किसानों को बहुत धोखा होता था। उसके लिए भी प्रधान मंत्री जी ने सभी प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों का बुलाकर यहां पर मीटिंग की, हमारे कृषि मंत्री जी ने भी मीटिंग की और मीटिंग करके राज्य सरकारों से कहा है कि किसान हमारा अन्नदाता है, उनके साथ जो धोखा होता है उस धोखे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ऐसी कोई कम्पनियां हैं, कोई सप्लायर्स हैं और डीलर्स हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें जेल में बंद करना चाहिए। इस प्रकार से उन पर दो तरह से मार पड़ती है-एक प्राकृतिक आपदा और दूसरा, नकली खाद, नकली बीज, नकली दवाइयों के कारण किसान को आत्म-हत्या के लिए उतारु होना पड़ता है। तो ये सब सारी बातें हैं, जो बुनियादी चीजें हैं। इन सब के ऊपर यू॰पी॰ए॰ सरकार ने ताकत के साथ, कठोरता के साथ यह बात कही है और इसके ऊपर कई राज्यों ने अमल भी किया है। तो ये सब सारी चीजें हैं और इन चीजों के साथ यह सारी स्थिति निर्मित होती है।

माननीय उपसाभाध्यक्ष जी, मैं इतना ही निवेदन करुंगा कि हमारे माननीय वी॰ नारायणसामी साहब जो एक किसान हैं और यहां हाऊस के सीनियर सदस्य हैं, उन्होंने देश के किसानों की दशा

देखकर और उनकी बातों के संबंध में यहां रिजाल्यूशन लाकर माननीय सदस्यों को इस पर विचार करने का मौका दिया और यहां माननीय सदस्यों ने जितने अपने अमूल्य सुझाव दिए हैं, उनकी आत्मा की आवाज के साथ ये सारी बातें सामने आई हैं। निश्चय ही हमारा विभाग और यूपीएं सरकार इस बात के लिए इमानदारी के साथ कार्य करेगी कि किस तरह से हम किसानों की तस्वीर को बदल सकें, उनके घर में हम कैसे खुशहाली ला सकते हैं, कैसे उनके बाल-बच्चों का जीवन सुधर सके, उनकी पढ़ाई-लिखाई, शादी-विवाह हो, इन सारी चीजों के साथ यूपीएं सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है।

महोदय, हम आपके माध्यम से सदन को विश्वास दिलाते हैं कि यहां जितनी बातें आई हैं उनके ऊपर हम मनन करेंग, तथा जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक लोग हैं उनके सामने आपके सुझाव रखकर अच्छी तरह से पेश करके आगे उस पर अमल करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे महोदय, समय के लिए आप भी इशारा कर रहे है। और देख रहें हैं, तो माननीय नारायणसामी साहब से अनुरोध करुंगा कि आप रिजाल्यूशन वापिस लें और हम आपसे प्रार्थना करते है।

SHRI V. NARAYANASAMY: Hon. Vice-Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity. The hon. Minister has intervened. I am grateful to him. I am grateful to the hon. Members who have participated in the discussion. Thirteen hon. Members participated in the discussion. They are Shri E.M. Sudarsana Naatchiappan, Shri Suresh Bhardwaj, Shri A. Vijayaraghavan, Shri Ravula Chandra Sekar Reddy, Shrimati Kum Kum Rai, Shri Harendra Singh Malik, Dr. Faguni Ram, Shri Jayantilal Barot, Dr. M.S. Gill, Dr. Gyan Prakash Pilania, Shri Sharad Anantrao Joshi, Dr. (Shrimati) Prabha Thakur and Shri Moolchand Meena. I am very grateful to all the hon. Members. The entire House has shown its concern for the farmers. Every part of my Resolution was discussed by the hon. Members. They gave their viewpoints about how to mitigate the sufferings of farmers. It is a universal phenomenon that the farmer is at the receiving end. We all speak about them. I am not going into any party-political consideration. Every political party tells the people that they are for the *Kisans*. Every governments tells them that they are for the welfare of the farmers. In the country, 70 per cent people belong to the farming community. They are the creators of economy of this country. But the benefit is taken away by industrialists and the business community. Whatever is produced by farmers, that goes to the industry and the market. The intermediaries, the businessmen earn income out of it and the farmer is at a loss. Whether at the production

stage or when the produce goes to the market, the farmers are the worst sufferers. Moreover, earlier the farmers were given subsidy for fertilizers, seeds, etc. They were given subsidy for implements also. Gradually, in the name of modernisation and in the name of a changed-economy, some of the benefits have been withdrawn. In the world economic forum, that is WTO, we have been fighting so that our farmers can get their due. The reason is, the Western countries, the developed countries, are giving more than 70 per cent subsidy to the farmers because they want the produce to go up. They know that if they don't do it the farmers will stop cultivation in those countries. The United States is giving more than 60 per cent subsidy to their farmers. The European countries are also giving subsidy to the farmers. Now the suggestion which I have made is this. We have discussed in this august House one issue of reducing rate of interest on bank loans, whether it is the cooperative institution or a bank. The hon. Finance Minister was trying to defend himself, but in vain. The hon. Finance Minister said that the money was going to the cooperative banks at an interest rate of 5.5 per cent and then they add their cost overheads and that it comes to 16 to 17 per cent; but up to Rs. 50,000, we are giving loan at an interest rate of 9 per cent. That is what the Finance Minister said. The cost of input for farmers is very high. They are all small farmers because they are having small holdings up to two acres of land. In our country rich farmers are not more than 5 to 6 per cent. Up to Rs. 3 lakhs, the rate of interest should be very low. If we compare it with the Western countries, in the Western countries the rate of interest is 1 to 2 per cent, even for agriculture. An hon. Member rightly put a question to the Finance Minister that when you are giving loan for purchasing a vehicle, for purchasing a house, for purchasing a refrigerator and other things at zero per cent interest rate, why should it not be for agriculture also? The farmer is overburdened because of the compounding interest. Therefore, they are committing suicides. We want that the farmers should be relieved of their indebtedness. I have got with me a sample survey conducted by an organisation. In Andhra Pradesh alone, 82 per cent of the farmers are in debt. In Tamil Nadu, 74.5 per cent farmers are in debt. They are indebted to whom. They are indebted to private moneylenders, apart from banks. So far as Punjab is concerned, the number is 65.4 per cent; in the case of Kerala, it is 64.4 per cent; in the case of Karnataka, it is

61.6 per cent and in the case of Maharashtra, it is 54.8 per cent. The basic reason for committing suicide is, the farmers are indebted to private moneylenders. The private moneylenders are squeezing them. The farmers are unable to repay the money. Therefore, they are going to the extent of ending their life. So, until and unless the Government supports the farmers in raising their crops, suicides cannot stop. Otherwise, the private moneylenders go to the farmers and give them money. The innocent farmers take money from then, and they get into the debt trap.

As the Finance Minister mentioned, the co-operative system—the system itself is in shambles—has to be revamped. The hon. Prime Minister has allocated Rs. 35 crores for revamping the co-operative system in the country. In various places, I have seen that the co-operative banks and co-operative institutions have become somebody's private property.

Federalism is not there; the democratic system is not here in the co-operative system. Unless and until the Cooperatives Act is amended and a stringent law is brought, it will become somebody's own property and our poor farmers cannot enjoy the fruit of it. And, the theory of co-operative system itself will change.

Sir, since the hon. Minister has said that he would take note of the suggestions by various hon. Members, I would only mention in brief the suggestions that I wish to place before him. No.1 is compensatory insurance; No.2 is increasing the subsidy; No.3 is farmers' credit policy and No.4 is technology upgradation. Now, when we talk about lab to land, in our country, we have seen that even though a lot of inventions have been made, it takes eight to ten years—the hon. S & T Minister is here—for any invention to reach the farmers. By then the whole system changes and the benefit does not accrue to them. Therefore, the lab to land has to be immediately adopted. Also, there should be cold storage facility made available to farmers. Good market intervention by the Government is also very important. Otherwise, it will only benefit the middlemen and the businesmen. Therefore, unless and until market intervention by the Government is there, it will be very difficult for any farmer to survive. Sir, I am sure that the hon. Minister has taken note of our suggestions, and he would, in due consultation with the Finance Minister, evolve the credit policy for the farmers. That is very important.

Only then will we be able to save the farmers from committing suicides, and we will also be able to develop the farming community. I know that it will take a long time, but, at least, you have to make a beginning. As of now, let the farmers be relieved of their debt.

Sir, with these words, since the hon. Minister has requested me to withdraw my Resolution, I hope he will accept my suggestions and other suggestions made by my colleagues and that he will implement them.

The Resolution was, by leave, withdrawn.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Shri Datta Meghe to move his Resolution.

Providing Special Economic Package for the Development of the Vidarbha Region

श्री दत्ता मेघे (महाराष्ट्र): महोदय: मैं निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करता हूं कि:

"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का एक पिछड़ा क्षेत्र है, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह इस क्षेत्र के और तीव्र विकास के लिए एक विशेष कार्य योजना बनाए और विशेष कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करे।"

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): We will take up the discussion on the next Private Members' Resolution day.

Now, the House is adjourned till 11 a.m. on Monday, the 27th February, 2006.

The House then adjourned at fifty-nine minutes past four of the clock, till eleven of the clock on Monday, the 27th February, 2006.

MGIPMRND—984RS—30-9-2006.